www.railsamacharbureauald.com

सम्पूर्ण भारतीय रेल जगत का प्रथम पाक्षिक, प्रयागराज से प्रकाशित

रेल समाचार ब्यूरो

सन् 1990 से रेल सेवा में समर्पित

आजादी के बाद, भारतीय रेल की हर यात्रा, भारत की प्रगति की कहानी कहती है। तिरंगे के साथ, यह प्रगति का पहिया कभी न रुके। जय हिन्द!

भारतीय रेल की हर यात्रा एकता का प्रतीक है, जो अलग-अलग संस्कृतियों को एक साथ लेकर चलती है-ठीक वैसे ही जैसे हमारी स्वतंत्रता ने पूरे देश को एक सूत्र में पिरोया है।

वर्ष-35 अंक:15-16 रेल समाचार ब्यूरो प्रयागराज 01-31 अगस्त 2025 पृष्ठ 12 (संयुक्तांक) मूल्य:20 रु. मात्र. डाक खर्च (रंगीन सहित)

सशक्त भारत की ओर: तेजी से रफ्तार पकड़ रहा है भारतीय रेल नेटवर्क

दुर्गम से सुगम: उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक से बढ़ा विकास का सफर

- उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक सबसे कठिन परियोजनाओं में से एक होने के बावजूद, न केवल पर्याप्त वैश्विक सुरक्षा प्रावधान प्रदान करता है, बल्कि यह हिमालयी पारिस्थितिकी को भी संरक्षित करता है- रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव।
- परियोजना के दौरान 215 किलोमीटर से अधिक सड़कों के निर्माण से स्थानीय आबादी के लिए संपर्क में सुधार के साथ रोजगार सृजन भी हुआ

सूत्र/रे.स.ब्यू- कुल 272 किलोमीटर लंबाई वाली उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक (यूएसबीआरएल) परियोजना हाल ही में चालू की गई है। रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी कि यूएसबीआरएल परियोजना, आजादी के बाद देश में शुरू की गई सबसे कठिन नई रेल लाइन परियोजनाओं में से एक है। यह भूभाग युवा हिमालय से होकर गुजरता है, जो भूवैज्ञानिक विविधताओं और असंख्य समस्याओं से भरा है। इस परियोजना में रेलवे ने जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले में चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाया है। प्रतिष्ठित चिनाब पुल 1315 मीटर लंबा है, इसका आर्च स्पान 467 मीटर है और नदी तल से इसकी ऊंचाई 359 मीटर है। इस परियोजना में अंजी खड्ड पर भारतीय रेलवे का पहला केबल-स्टेड पुल बनाया गया है। इसका ब्रिज डेक नदी तल से घघज्ञ मीटर ऊंचा है और इसके मुख्य तोरण की ऊंचाई 193 मीटर है। इस परियोजना ने क्षेत्र में महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक योगदान दिया है, इसमें रोजगार सृजन भी एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। इस परियोजना ने 5 करोड़ से ज़्यादा मानव- दिवस रोजगार सृजित किया है। यूएसबीआरएल परियोजना के सामाजिक-आर्थिक विकास प्रयासों का एक और महत्वपूर्ण पहलू 215 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी सड़कों का निर्माण रहा है, इसमें एक सुरंग और 320 छोटे पुलों का निर्माण शामिल है। इस सड़क नेटवर्क ने स्थानीय लोगों को अन्य क्षेत्रों से संपर्क बढ़ाने और सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाने में मदद की है। अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप, यूएसबीऋ आरएल परियोजना में पर्याप्त सुरक्षा प्रावधान किए गए हैं। 2 किलोमीटर से अधिक लंबी सभी सुरंगों में वायु की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए यांत्रिक वेंटिलेशन सिस्टम लगाए गए हैं। सभी सुरंगों में संभावित आग की घटनाओं से तुरंत निपटने और उन्हें नियंत्रित करने के लिए अग्नि हाइड्रेंट और अग्निशामक यंत्रों सहित अग्निशमन प्रणालियां उपलब्ध कराई गई हैं। इसके अलावा, यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, 3 किलोमीटर से अधिक लंबी सुरंग में निकास सुरंगें भी बनाई गई हैं। इस परियोजना में कुल 66 किलोमीटर की निकास सुरंगें बनाई गई हैं। हिमालयी पारिस्थिति की में न्यूनतम व्यवधान सुनिश्चित करने के लिए, ढलान स्थिरीकरण पर उचित ध्यान दिया गया है और इस परियोजना के क्रियान्वयन हेतु विश्व के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों को शामिल किया गया है। प्राकृतिक भू-भागों के क्षरण और क्षति को रोकने के लिए, नीरी के दिशानिर्देशों और विस्तृत डिजाइन सलाहकारों के सुझावों के अनुसार ढलान स्थिरीकरण हेतु व्यापक योजनाएं लागू की गई हैं। चिनाब पुल पर ढलान स्थिरता का डिजाइन भारतीय विज्ञान संस्थान, बैंगलोर और आईआईटी/दिल्ली द्वारा तैयार किया गया था। चिनाब पुल पर ढलान स्थिरता की स्वतंत्र जांच के लिए ऐसे कार्यों का अनुभव रखने वाली अन्य वैश्विक फर्मों को जिम्मेदारी दी गई थी। अंजी पुल पर ढलान स्थिरता का डिजाइन और प्रमाण-जांच का काम भी अनुभवी वैश्विक फर्मों द्वारा किया गया। इसके अलावा, चिनाब और अंजी खड्ड पुलों सहित कटरा-काजीगुंड नई रेल लाइन के निर्माण से होने वाले पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन भी राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान (नीरी), नागपुर द्वारा किया गया है। नीरी द्वारा तैयार पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) के आधार पर व्यापक सुरक्षा उपाय और शमन उपाय लागू किए गए हैं। सुरंग से निकली सामग्री के प्रबंधन हेतु, प्राकृतिक नालों में पानी छोड़ने से पहले, सुरंग के निकास द्वारों पर अवसादन टैंक बनाए गए हैं। जिन गांवों में रिवर्स पंपिंग के कारण प्राकृतिक जल स्रोत बाधित हो गए थे, वहां वैकल्पिक जल स्रोत उपलब्ध कराए गए। सतही जल का सुचारू प्रवाह सुनिश्चित करने और मलबा यार्डों में कटाव को रोकने के लिए आवश्यक स्थानों पर उचित पंक्तिबद्ध नालियां और सीढ़ीदार ढलान बनाए गए। सुरंग निर्माण के दौरान कंपन और पर्यावरणीय क्षति को न्यूनतम रखने के लिए नियंत्रित विस्फोट की उन्नत तकनीकों का उपयोग किया गया। कटरा-बनिहाल खंड की सभी सुरंगों में परिचालन चरण के दौरान भी वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए सेंसर लगाए गए हैं। पूरी रेल परियोजना सुरंगों और खुले खंडों में ओवरहेड कंडक्टर प्रणाली के उपयोग से विद्युतीकृत की गई है। रेल परिवहन सबसे पर्यावरण-अनुकूल परिवहन साधन है, जो डीजल की तुलना में कार्बन उत्सर्जन को काफी कम करता है। यद्यपि जैव विविधता संरक्षण के विशिष्ट उपायों को ईएमपी में रेखांकित किया गया है, समग्र पर्यावरणीय शमन प्रयास स्थानीय पारिस्थिति की की रक्षा में योगदान करते हैं। डंपिंग स्थलों पर वृक्षारोपण गतिविधि के लिए स्थल तैयारी दिशानिर्देशों में स्थानीय प्रजातियों के पौधे लगाना और पारिस्थिति की-पुनर्स्थापन के लिए घास लगाना शामिल है। घाटी वाले हिस्से की शेष भारतीय रेल नेटवर्क के साथ सभी मौसमों के अनुकूल, विश्वसनीय और आरामदायक रेल कनेक्टिविटी के साथ, पर्यटन को काफी बढ़ावा मिलेगा।

राष्ट्र की धमनियां: भारतीय रेल, भारत के विकास का अनवरत वाहक

सूत्र/रे.स.ब्यू- आज जब भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, तब इस विकास की बुनियाद में उन स्तंभों को याद करना आवश्यक हो जाता है जिन्होंने चुपचाप, दशकों से इस राष्ट्र को गति दी है। इनमें भारतीय रेल का स्थान सर्वोपरि है। मात्र एक परिवहन माध्यम न होकर, भारतीय रेल देश की जीवनरेखा है, एक ऐसी धमनी जिसने सुदूर क्षेत्रों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा है और भारत की सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक एकता को अपने फौलादी धागों से बुना है। 16 अप्रैल, 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच चली पहली रेलगाड़ी ने केवल 34 किलोमीटर की दूरी तय नहीं की थी, बल्कि उसने भारत के औद्योगीकरण और एकीकरण के एक नए युग का सूत्रपात किया था। स्वतंत्रता के बाद, बिखरी हुई रियासतों को एक राष्ट्र के रूप में पिरोने में रेलवे की भूमिका ऐतिहासिक रही। इसने न केवल भौगोलिक दूरियों को कम किया, बल्कि भाषाई और सांस्कृतिक भिन्नताओं के बीच संवाद का एक ऐसा पुल बनाया, जिसने 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' की संकल्पना को साकार किया। देश के किसी भी कोने में बैठा व्यक्ति आज आसानी से दूसरे छोर तक यात्रा कर सकता है, जो राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत करता है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो भारतीय रेल देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। यह केवल यात्रियों को ही नहीं, बल्कि कोयला, इस्पात, सीमेंट, खाद्यान्न और उर्वरक जैसे आवश्यक संसाधनों को देश के कोने-कोने में पहुँचाती है। समर्पित फ्रेट कॉरिडोर जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के माध्यम से माल ढुलाई को तीव्र और सस्ता बनाकर रेलवे 'मेक इन इंडिया' अभियान को धरातल पर सफल बना रही है। यह लाखों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करती है, जिससे यह दुनिया के सबसे बड़े नियोक्ताओं में से एक है। कृषि क्षेत्र में भी इसका योगदान अतुलनीय है। किसानों की उपज को समय पर बाजारों तक पहुँचाकर यह सुनिश्चित करती है कि देश का कोई भी हिस्सा अन्न से वंचित न रहे। समय के साथ भारतीय रेल ने खुद को निरंतर आधुनिक और प्रासंगिक बनाए रखा है। भाप के इंजनों से लेकर आज की सेमी-हाई-स्पीड 'वंदे भारत' और भविष्य की 'बुलेट ट्रेन' तक का सफर, भारत की तकनीकी प्रगति और आत्मनिर्भरता का जीता-जागता प्रमाण है। स्टेशनों का आधुनिकीकरण, 'अमृत भारत स्टेशन योजना' के तहत विश्वस्तरीय सुविधाओं का विकास और डिजिटल टिकटिंग प्रणाली ने यात्रियों के अनुभव को पूरी तरह बदल दिया है। यह परिवर्तन केवल गति और सुविधा तक सीमित नहीं है, बल्कि सुरक्षा और संरक्षा पर भी अभूतपूर्व ध्यान दिया जा रहा है, ताकि हर यात्रा सुरक्षित और सुखद हो। आज जब विश्व पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास की बात कर रहा है, तब भारतीय रेल विद्युतीकरण की दिशा में तेजी से आगे बढ़कर कार्बन उत्सर्जन को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। यह परिवहन का एक पर्यावरण-अनुकूल साधन है जो सड़कों पर वाहनों का बोझ कम करता है और प्रदूषण को नियंत्रित करने में सहायक है। निष्कर्षत:, भारतीय रेल का योगदान केवल आंकड़ों और किलोमीटरों में नहीं मापा जा सकता। यह करोड़ों भारतीयों की आकांक्षाओं का वाहक है, जो उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य और अवसरों के नए केंद्रों से जोड़ता है। यह वह शक्ति है जो भारत की विविधता को एक सूत्र में बांधती है और राष्ट्र के विकास के पहियों को अनवरत गति प्रदान करती है। जैसे-जैसे भारत एक विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है, भारतीय रेल निस्संदेह इस यात्रा में अपने सबसे विश्वसनीय और शक्तिशाली भागीदार के रूप में अपनी भूमिका निभाती रहेगी।

दिवाली और छठ की छुट्टियां परिवार के साथ बिताने व काम से 5 हफ्ते का अवकाश लेने के इच्छुक लोगों के लिए खुशखबरी

रेलवे ने भीड़ को कम करने के लिए राउंड ट्रिप पैकेज के लिए वापसी यात्रा के मूल किराए पर 20% की छूट शुरू की

सूत्र/रे.स.ब्यू- भारतीय रेल भीड़ से बचने, परेशानी मुक्त बुकिंग सुनिश्चित करने के साथ-साथ यात्रियों की सुविधा के लिए प्रयास कर रही है। त्योहारों के मौसम में भीड़भाड़ को कम करने और विशेष ट्रेनों सहित रेलगाड़ियों का दोनों तरफ से उपयोग सुनिश्चित करने के लिए रियायती किराए पर राउंड ट्रिप पैकेज नामक प्रायोगिक योजना तैयार करने का निर्णय लिया गया है।

यह योजना उन यात्रियों पर लागू होगी जो नीचे दी गई निर्धारित अवधि के दौरान अपनी वापसी यात्र भी चुनते हैं:

●)इस योजना के तहत, समान यात्रियों के समूह के लिए आगे और वापसी दोनों यात्राओं के लिए बुकिंग करने पर छूट लागू होगी। वापसी यात्रा का यात्री विवरण आगे की यात्रा के समान होगा।

●)एआरपी तिथि 13 अक्टूबर 2025 के लिए बुकिंग प्रारंभ तिथि 14.08.2025 होगी। आगे की टिकट पहले 13 अक्टूबर 2025 और 26 अक्टूबर 2025 के बीच ट्रेन प्रारंभ तिथि के लिए बुक की जाएगी और बाद में 17 नवंबर और 1 दिसंबर 2025 के बीच ट्रेन प्रारंभ तिथि के लिए कनेक्टिंग यात्रा सुविधा का उपयोग करके वापसी यात्रा टिकट बुक की जाएगी। वापसी यात्रा की बुकिंग के लिए अग्रिम आरक्षण अवधि लागू नहीं होगी।

●)उपरोक्त बुकिंग केवल दोनों दिशाओं के कन्फर्म टिकटों पर ही मान्य होगी।

●)वापसी यात्रा के मूल किराए पर केवल 20% की कुल छूट दी जाएगी।

●)इस योजना के अंतर्गत बुकिंग आगे और वापसी दोनों यात्राओं के लिए समान श्रेणी और समान ओ-डी जोड़ी के लिए होगी।

●)इस योजना के अंतर्गत बुक किए गए टिकटों के लिए किराया वापसी की अनुमति नहीं होगी।

●)उपर्युक्त योजना फ्लेक्सी किराया वाली ट्रेनों को छोड़कर सभी श्रेणियों और विशेष ट्रेनों (मांग पर ट्रेनें) सहित सभी रेलगाड़ियों में मान्य होगी।

●)किसी भी यात्रा में इन टिकटों में कोई संशोधन नहीं किया जाएगा।

●)रियायती किराए पर वापसी यात्रा बुकिंग के दौरान कोई छूट, रेल यात्रा कूपन, वाउचर आधारित बुकिंग, पास या पीटीओ आदि स्वीकार्य नहीं होंगे।

(●)आगे और वापसी यात्रा के टिकट एक ही माध्यम से बुक किए जाने चाहिए:

● इंटरनेट (ऑनलाइन) बुकिंग, या

● आरक्षण कार्यालयों में काउंटर बुकिंग

●)इन पीएनआर के लिए चार्टिंग के दौरान यदि कोई अतिरिक्त किराया वसूली होती है, तो कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

17 नवंबर से 1 दिसंबर 2025 तक बुक की गई रियायती वापसी यात्रा टिकटों पर वर्तमान 60 दिनों की अग्रिम आरक्षण अवधि लागू नहीं होगी

ट्रेनों में भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता बेहतर करने के लिए आईआरसीटीसी द्वारा सटीक निगरानी प्रणालियाँ और अनुपालन उपाय लागू किए गए हैं: अश्विनी वैष्णव

सूत्र/रे.स.ब्यू- ट्रेनों में भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता में सुधार लाने के मकसद से, रेल मंत्रालय ने 2023 के वाणिज्यिक परिपत्र संख्या 24 के माध्यम से निर्देश जारी किए हैं। इसमें किसी एक ट्रेन के स्थान पर, ट्रेनों के समूहों के लिए अनुबंध प्रदान करने की बात कही गई है। बुनियादी ढाँचे के विकास और ट्रेन में भोजन उत्पादन और सेवाओं की संपूर्ण जवाबदेही तय करने पर जोर दिया गया है। आईआरसीटीसी ने मौजूदा नीति दिशानिर्देशों के ढांचे के तहत, ट्रेनों में भोजन की आपूर्ति के लिए बेस किचन शुरू करने हेतु, स्थानों की पहचान के साथ-साथ रूट-वार ट्रेनों के समूह बनाए हैं। निविदा दस्तावेजों में निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार, आईआरसीटीसी द्वारा पारदर्शी प्रक्रिया के जरिए, उच्चतम बोली लगाने वालों को ट्रेनों के समूहों के अनुबंध प्रदान किए गए हैं। ठेकेदारों द्वारा निविदा शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने और किसी भी ठेकेदार को किसी भी अनैतिक व्यवहार या अनुचित लाभ मिलने से रोकने के लिए, आईआरसीटीसी द्वारा मजबूत निगरानी प्रणाली और अनुपालन उपाय लागू किए गए हैं। आईआरसीटीसी द्वारा जारी ट्रेनों के समूहों के लिए निविदाओं में, कुल 24 बोलीदाताओं ने भाग लिया, जिनमें से 20 संस्थाओं को आईआरसीटीसी ने अनुबंध प्रदान किए हैं। निविदा शर्तों के विपरीत आईआरसीटीसी ने कोई भी अनुबंध नहीं दिया है। विभिन्न सेवा प्रदाताओं को जारी किए गए लेटर ऑफ अवार्ड (एलओए) का विवरण आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया है। आज तक किसी भी सफल बोलीदाता को क्लस्टर ए के 80% अनुबंध नहीं मिले हैं। रेलवे द्वारा विभिन्न स्तरों पर हितधारकों, निर्वाचित प्रतिनिधियों, केटरिंग संघों, व्यक्तियों आदि से प्रस्तुतिकरण, सुझाव, शिकायतें आदि प्राप्त करना एक सतत् प्रक्रिया है। इन शिकायतों की गुण-दोष के आधार पर जाँच की जाती है और उसी के मुताबिक जरुरी कार्रवाई की जाती है। वर्ष 2024-25 में, आईआरसीटीसी को प्राप्त शिकायतों पर 13.2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया। इसके अलावा, रेलमदद पोर्टल पर शिकायतों की निरंतर निगरानी भी की जाती है। भारतीय रेल नेटवर्क पर रोजाना औसतन 16.5 लाख भोजन परोसा जाता है। भारतीय रेल की कोशिश है कि मुसाफिरों को इतनी बड़ी मात्रा में भी भोजन की सुचारू और निर्बाध सेवाएँ मिल सकें। यात्रियों को दी जाने वाली समग्र सेवाओं में सुधार के लिए समय-समय पर आवश्यक उपाय किए जाते हैं। सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए, परिपत्र में कई प्रावधान किए गए हैं, जिनमें खानपान सेवाओं के प्रबंधन के लिए तैनात किए जाने वाले कर्मचारियों की योग्यता और प्रशिक्षण संबंधी निर्देश शामिल हैं। इन सेवाओं की देखरेख और निगरानी के लिए होटल प्रबंधन स्नातकों को तैनात करना जरुरी किया गया है। इसी प्रकार, आईआरसीटीसी/ठेकेदारों द्वारा डिग्री/डिप्लोमा हॉस्पिटैलिटी मॉनिटर नियुक्त किए जाते हैं: रसोई संचालन की निगरानी के लिए विभिन्न रसोई घरों में 819 और ट्रेनों में ऑन-बोर्ड खानपान सेवाओं की निगरानी के लिए 876 तैनात किए जाते हैं।

बेहतर आईआरसीटीसी भोजन सेवाओं के लिए 1695 होटल प्रबंधन स्नातक, बेस किचन और ऑन-बोर्ड कैटरिंग की देखरेख और निगरानी कर रहे हैं। भारतीय रेलवे अपने नेटवर्क में प्रतिदिन 16.5 लाख भोजन परोसता है, जबकि आईआरसीटीसी ने शिकायतों पर पिछले वित्तीय वर्ष में 13.2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है।

क्लाउड टेक्नोलॉजी से सशक्त रेलवन ऐप, टिकट बुकिंग का अनुभव बदलेगा

यात्री हाल ही में आरंभ किए गए रेल मोबाइल ऐप के माध्यम से कहीं भी किसी भी समय आरक्षित और अनारक्षित ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं

सूत्र/रे.स.ब्यू- रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में बताया कि भारतीय रेलवे, रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र (सी.आर.आई.एस.) के माध्यम से यात्री आरक्षण प्रणाली (पी.आर.एस.) का पूर्ण नवीनीकरण कर रहा है। पी.आर.एस. के नवीनीकरण में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क उपकरण, सुरक्षा अवसंरचना और कार्यात्मकताओं का उन्नयन और प्रतिस्थापन शामिल है, जिसका डिजाइन नई सुविधाओं को संभालने में सक्षम है। वर्तमान पीआरएस प्रणाली 2010 में स्थापित की गई थी और यह आइटेनियम सर्वर और ओपन वीएमएस (वर्चुअल मेमोरी सिस्टम) पर चलती है। वर्तमान पीआरएस प्रणाली को पारंपरिक प्रौद्योगिकी प्रणालियों से नवीनतम क्लाउड प्रौद्योगिकी-संगत प्रणालियों में अपग्रेड करने की आवश्यकता है। पिछले कुछ वर्षों में, यात्रियों की प्राथमिकताएँ और आकांक्षाएँ बदली हैं। आधुनिक पीआरएस का उद्देश्य यात्रियों की बढ़ी हुई आकांक्षाओं को पूरा करना है। रेलवे ने हाल ही में रेलवन ऐप शुरू किया है। इस ऐप के जरिए यात्री अपने मोबाइल फोन पर आरक्षित और अनारक्षित दोनों तरह के टिकट बुक कर सकते हैं। इससे पी.आर.एस. सुविधा यात्रियों की पहुँच में आ गई है। पहले, ट्रेनों में आरक्षित टिकट बुक करने के लिए 120 दिनों की अग्रिम आरक्षण अवधि (ए.आर.पी.) होती थी। 1 नवंबर 2024 से, यात्रा की तारीख को छोड़कर, ए.आर.पी. को घटाकर 60 दिन कर दिया गया है। यह बदलाव बुकिंग के रुझान को ध्यान में रखते हुए और अप्रत्याशित घटनाओं के कारण रद्दीकरण को कम करने के लिए किया गया है। बुकिंग के रुझान और फीडबैक के आधार पर अग्रिम आरक्षण अवधि (ए.आर.पी.) में बदलाव एक सतत और जारी रहने वाली प्रक्रिया है। वर्तमान पी.आर.एस. प्रति मिनट लगभग 25,000 टिकट बुक कर सकता है और नई प्रणाली इस क्षमता से चार गुना अधिक क्षमता के लिए डिजाइन की गई है।

यात्री वरीयताओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए वर्तमान यात्री आरक्षण प्रणाली को मौजूदा 25,000 से प्रति मिनट से बढ़ाकर 1,00,000 से अधिक टिकटों को संभालने के लिए अपग्रेड किया जा रहा है अप्रत्याशित घटनाओं के कारण रद्दीकरण को कम करने और बुकिंग प्रवृत्ति के साथ संरेखित करने के लिए अग्रिम आरक्षण अवधि को 120 दिनों से घटाकर 60 दिन किया

आत्मनिर्भरता ही विकसित भारत का आधार: प्रधानमंत्री मोदी

सूत्र/रे.स.ब्यू- 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 'आत्मनिर्भर भारत' को 2047 तक 'विकसित भारत' के निर्माण का एक प्रमुख आधार स्तंभ बताया। उन्होंने रक्षा, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, और विनिर्माण सहित विभिन्न क्षेत्रों में देश की प्रगति पर प्रकाश डालते हुए आत्मनिर्भरता को राष्ट्रीय शक्ति, सम्मान और रणनीतिक स्वायत्तता का मूलमंत्र करार दिया।

रक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता

प्रधानमंत्री ने 'ऑपरेशन सिंदूर' का उल्लेख करते हुए इसे रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता का प्रतीक बताया। उन्होंने जोर देकर कहा कि स्वदेशी क्षमताएं और भारत में निर्मित हथियार देश को किसी भी खतरे से निर्णायक रूप से निपटने में सक्षम बनाते हैं। इसी क्रम में, उन्होंने ''मिशन सुदर्शन चक्र'' के शुभारंभ की भी घोषणा की, जिसका उद्देश्य दुश्मन की रक्षा घुसपैठ को विफल करना और भारत की आक्रामक क्षमताओं को बढ़ाना है। युवाओं का आह्वान करते हुए उन्होंने भविष्य की रक्षा प्रौद्योगिकी को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत में ही जेट इंजन विकसित करने का आग्रह किया।

प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष में ऊंची उड़ान

तकनीकी आत्मनिर्भरता पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि भारत 2025 के अंत तक 'मेड इन इंडिया' सेमीकंडक्टर चिप्स लॉन्च करेगा। उन्होंने वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा और ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे क्षेत्रों में नवाचार की आवश्यकता पर बल दिया। अंतरिक्ष के क्षेत्र में, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए, उन्होंने भारत के अपने अंतरिक्ष स्टेशन की महत्वाकांक्षी योजना का एलान किया। उन्होंने बताया कि 300 से अधिक स्टार्टअप उपग्रह और अंतरिक्ष अन्वेषण में सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं, जो इस क्षेत्र में भारत की अग्रणी भूमिका को दर्शाता है।

ऊर्जा स्वतंत्रता की ओर बढ़ते कदम

प्रधानमंत्री मोदी ने ऊर्जा स्वतंत्रता को युवाओं के भविष्य और किसानों के कल्याण के लिए आवश्यक बताया। उन्होंने घोषणा की कि भारत ने 2030 तक 50% स्वच्छ ऊर्जा का लक्ष्य समय से पांच साल पहले, 2025 में ही हासिल कर लिया है। उन्होंने बताया कि सौर, परमाणु, जलविद्युत और हाइड्रोजन ऊर्जा को उन्नत किया जा रहा है। निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से परमाणु ऊर्जा का विस्तार किया जाएगा, और स्वतंत्रता के 100वें वर्ष तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को दस गुना बढ़ाने का लक्ष्य है। इसके अतिरिक्त, 'राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन' और 'राष्ट्रीय गहरे जल अन्वेषण मिशन' के माध्यम से ऊर्जा संसाधनों में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित की जाएगी।

कृषि, उद्योग और नवाचार

किसानों को सशक्त बनाने और खाद्य सुरक्षा के लिए, प्रधानमंत्री ने देश में ही उर्वरकों के उत्पादन की आवश्यकता पर बल दिया ताकि आयात पर निर्भरता कम हो सके। उन्होंने नागरिकों और दुकानदारों से ''वोकल फॉर लोकल'' पहल के तहत स्वदेशी उत्पादों को गर्व के साथ अपनाने का आग्रह किया। दवा क्षेत्र में भारत की ''दुनिया की फार्मेसी'' के रूप में भूमिका पर प्रकाश डालते हुए, उन्होंने अनुसंधान एवं विकास में अधिक निवेश का आह्वान किया ताकि मानवता के लिए सर्वोत्तम और सबसे सस्ती दवाइयाँ भारत में ही बन सकें। साथ ही, उन्होंने युवाओं से भारत के अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विकसित करने का भी आग्रह किया ताकि देश की डिजिटल संप्रभुता मजबूत हो सके।

दिल्ली-मुंबई मार्ग के मथुरा-कोटा सेक्शन पर कवच 4.0 प्रणाली लागू।

सूत्र/रे.स.ब्यू- भारतीय रेलवे ने व्यस्त यातायात वाले दिल्ली-मुंबई मार्ग के मथुरा-कोटा सेक्शन पर स्वदेशी रेलवे सुरक्षा प्रणाली कवच 4.0 स्थापित कर दी है। यह देश में रेलवे सुरक्षा प्रणालियों के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ''माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 'आत्मनिर्भर भारत' दृष्टिकोण से प्रेरणा लेते हुए, रेलवे ने कवच स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली का स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकास और निर्माण किया है। कवच 4.0 एक प्रौद्योगिकी-प्रधान प्रणाली है। इसे अनुसंधान डिजाइन एवं मानक संगठन (आरडीएसओ) द्वारा जुलाई 2024 में अनुमोदित किया गया था। कई विकसित देशों को ट्रेन सुरक्षा प्रणालियों को विकसित करने और स्थापित करने में 20-30 साल लग गए। कोटा-मथुरा सेक्शन पर कवच 4.0 की कमीशनिंग बहुत ही कम समय में पूरी हो गई है। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।'' आजादी के बाद पिछले 60 वर्षों में देश में अंतर्राष्ट्रीय मानकों की उन्नत रेल सुरक्षा प्रणालियाँ स्थापित नहीं की गई थीं। रेल और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, कवच प्रणाली हाल ही में शुरू की गई है। भारतीय रेल छह वर्षों की छोटी सी अवधि में देश भर के विभिन्न मार्गों पर कवच 4.0 को लागू करने की तैयारी कर रही है। कवच प्रणाली पर 30,000 से अधिक लोगों को पहले ही प्रशिक्षित किया जा चुका है। आईआरआईएसईटी (भारतीय रेल सिग्नल इंजीनियरिंग एवं दूरसंचार संस्थान) ने कवच को अपने बी.टेक. पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए 17 एआईसीटीई- अनुमोदित इंजीनियरिंग कॉलेजों, संस्थानों और विश्वविद्यालयों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। कवच में लगाई गई प्रभावी ब्रेक प्रणाली से लोको पायलटों को रेल की गति बनाए रखने में मदद मिलेगी। कोहरे जैसी कम दृश्यता की स्थिति में भी, लोको पायलटों को सिग्नल के लिए केबिन से बाहर देखने की आवश्यकता नहीं होगी। पायलट केबिन के अंदर लगे डैशबोर्ड पर जानकारी देख सकते हैं।

Scan the Code for the Latest Verified
RAILWAYS NEWS ON OUR WEBSITE OR E-PAPER

हमारी वेबसाइट या ई-पेपर पर भारतीय रेलवे के सत्यापित समाचार को पढ़ने के लिए कोड को स्कैन करें

www.railsamacharbureauald.com

SCAN QR

त्योहारों में भीड़ प्रबंधन के लिए रेलवे की नई रणनीति, स्टेशन निदेशकों को मिलेगा विशेष अधिकार

भारी भीड़ की स्थिति में भीड़भाड़ कम करने के लिए प्रमुख स्टेशनों पर सीसीटीवी निगरानी, वॉकी-टॉकी, घोषणा प्रणालियाँ और वॉर रूम स्थापित किए जा रहे हैं

सूत्र/रे.स.ब्यू- त्योहारों के दौरान ट्रेनों में अत्यधिक भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रेलवे ने एक नई योजना लागू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत स्टेशन निदेशक को ट्रेनों की क्षमता और उपलब्धता के अनुसार टिकटों की बिक्री को सीमित करने जैसे "तत्काल भीड़भाड़ कम करने के निर्णय" लेने का अधिकार दिया जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि रेलवे स्टेशनों के बाहर चौड़े फुटओवर ब्रिज और स्थायी होल्डिंग एरिया बनाकर भीड़ प्रबंधन को और बेहतर बनाया जाएगा। वर्तमान में 5 स्टेशनों पर होल्डिंग एरिया के लिए पायलट प्रोजेक्ट प्रगति पर है। भारी भीड़ की स्थिति में प्रमुख स्टेशनों पर सीसीटीवी निगरानी, वॉकी-टॉकी, घोषणा प्रणालियाँ और वॉर रूम जैसी व्यवस्थाएँ स्थापित की जा रही हैं। इसके अलावा केवल कन्फर्म टिकट धारकों को ही प्लेटफॉर्म पर सीधे प्रवेश मिलेगा, जबकि बिना टिकट और प्रतीक्षा सूची वाले यात्रियों को ट्रेन आने तक बाहरी प्रतीक्षा क्षेत्र में रहना होगा।

भारतीय रेलवे ने रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की भारी भीड़ को संभालने के लिए निम्नलिखित कार्य योजना बनाई है: -

73 चिन्हित स्टेशनों पर स्थायी होल्डिंग क्षेत्रों का निर्माण:

- 2024 के त्यौहारी सीजन के दौरान, स्टेशनों के बाहर होल्डिंग एरिया बनाए गए थे। सूरत, उधना, पटना और नई दिल्ली में ये प्रतीक्षालय बड़ी भीड़ को संभालने में सक्षम थे। यात्रियों को केवल तभी प्रवेश दिया जाता था जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आती थी।
- महाकुंभ के दौरान प्रयाग क्षेत्र के नौ स्टेशनों पर भी ऐसी ही व्यवस्था की गई थी।
- इन स्टेशनों के अनुभव के आधार पर, देश भर के 73 स्टेशनों पर, जहाँ समय-समय पर भारी भीड़ होती है, स्टेशनों के बाहर स्थायी प्रतीक्षालय बनाने का निर्णय लिया गया है। प्रतीक्षालय के भीतर भीड़ को नियंत्रित किया जाएगा। यात्रियों को केवल तभी प्लेटफार्म पर जाने की अनुमति होगी जब ट्रेनें प्लेटफार्म पर आएँगी। इससे प्लेटफार्म पर भीड़ कम होगी।
- नई दिल्ली, आनंद विहार, वाराणसी, अयोध्या और गाजियाबाद स्टेशनों पर पायलट परियोजनाएं शुरू हो चुकी हैं।

प्रवेश नियंत्रण:

- 73 चिन्हित स्टेशनों पर पूर्ण प्रवेश नियंत्रण शुरू किया जाएगा।
- कन्फर्म आरक्षित टिकट वाले यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर सीधे प्रवेश दिया जाएगा।
- बिना टिकट वाले या प्रतीक्षा सूची वाले यात्री बाहरी प्रतीक्षालय में प्रतीक्षा करेंगे।
- सभी अनाधिकृत प्रवेश बिंदुओं को सील कर दिया जाएगा।

चौड़े फुट-ओवर-ब्रिज (एफओबी):

- 12 मीटर चौड़े (40 फीट) और 6 मीटर चौड़े (20 फीट) मानक चौड़े फुट- ओवर-ब्रिज एफओबी के दो नए डिजाइन विकसित किए गए हैं। रैंप युक्त ये चौड़े एफओबी महाकुंभ के दौरान भीड़ प्रबंधन में बेहद कारगर रहे। ये नए मानक चौड़े एफओबी सभी स्टेशनों पर लगाए जाएँगे।

कैमरे:

महाकुंभ के दौरान कैमरों ने भीड़ प्रबंधन में बड़े पैमाने पर मदद की। रेलवे स्टेशनों और आसपास के क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे रेलवे स्टेशनों पर भीड़ की कड़ी निगरानी और प्रबंधन में सहायक होंगे।

नये डिजाइन का आईडी कार्ड:

सभी कर्मचारियों और सेवाकर्मियों को नए डिजाइन का आईडी कार्ड दिया जाएगा ताकि केवल अधिकृत व्यक्ति ही स्टेशन में प्रवेश कर सकें।

कर्मचारियों के लिए नई डिजाइन की वर्दी:

- सभी कर्मचारियों को नई डिजाइन की वर्दी दी जाएगी ताकि संकट की स्थिति में उनकी आसानी से पहचान की जा सके।

> केवल कन्फर्म टिकट धारकों को ही प्लेटफॉर्म पर सीधे प्रवेश दिया जाएगा, बिना टिकट और प्रतीक्षा सूची वाले यात्रियों को ट्रेन आने तक बाहरी प्रतीक्षा क्षेत्र में रहना होगा भारी भीड़ की स्थिति में भीड़भाड़ कम करने के लिए प्रमुख स्टेशनों पर सीसीटीवी निगरानी, वॉकी-टॉकी, घोषणा प्रणालियाँ और वॉर रूम स्थापित किए जा रहे हैं।

युद्ध कक्ष:

बड़े स्टेशनों पर वॉर रूम विकसित किए जाएंगे। भीड़भाड़ की स्थिति में सभी विभागों के अधिकारी वॉर रूम में काम करेंगे।

नई पीढ़ी के संचार उपकरण:

सभी अत्यधिक भीड़ वाले स्टेशनों पर वॉकी-टॉकी, उद्घोषणा प्रणाली, कॉलिंग सिस्टम जैसे नवीनतम डिजाइन के डिजिटल संचार उपकरण लगाए जाएंगे।

स्टेशन निदेशक पद का उन्नयन:

- सभी प्रमुख स्टेशनों पर एक वरिष्ठ अधिकारी स्टेशन निदेशक के रूप में कार्यरत होंगे। अन्य सभी विभाग स्टेशन निदेशक को रिपोर्ट करेंगे।
- स्टेशन निदेशक को वित्तीय अधिकार दिए जाएँगे ताकि वे स्टेशन के सुधार के लिए तत्काल निर्णय ले सकें।

क्षमता के अनुसार टिकटों की बिक्री:

- स्टेशन निदेशक को स्टेशन और उपलब्ध ट्रेनों की क्षमता के अनुसार टिकटों की बिक्री को नियंत्रित करने का अधिकार होगा।

इसके अलावा, स्टेशनों पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अन्य हितधारकों के साथ समन्वय में निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:-

- भीड़ प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए जीआरपी/राज्य पुलिस और संबंधित रेलवे विभागों के साथ समन्वय किया जाता है।
- राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) और रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के कर्मचारियों को भीड़ को सुचारू रूप से नियंत्रित करने और यात्रियों को तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए संवेदनशील स्थानों पर तैनात किया जाता है।
- भारी भीड़ के दौरान भगदड़ जैसी स्थिति से बचने और यात्रियों को तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए भीड़ को सुचारू रूप से नियंत्रित करने हेतु जीआरपी और आरपीएफ कर्मचारियों को फुट-ओवर ब्रिज पर तैनात किया जाता है।
- भीड़ के बारे में सूचना एकत्र करने के लिए खुफिया इकाइयों (अपराध खुफिया शाखा (सीआईबी)/विशेष खुफिया शाखा (एसआईबी)) और सादे कपड़ों में कर्मचारियों को तैनात किया गया है और तदनुसार जीआरपी/पुलिस को शामिल करते हुए व्यवस्था की गई है।

संपादकीय: सच्ची देश सेवा: हमारी रेल, हमारी जिम्मेदारी

देशभक्ति केवल सीमा पर शौर्य दिखाने या बड़े कार्य करने तक सीमित नहीं है। सच्ची देश सेवा तो हमारे रोजमर्रा के छोटे-छोटे कर्मों में भी झलकती हैं हमारे नागरिक कर्तव्यों के पालन और राष्ट्र की संपत्ति के प्रति सम्मान में। इस भावना को जीवंत करती है हमारी भारतीय रेल। भारतीय रेल केवल परिवहन का साधन नहीं, बल्कि देश की जीवन-रेखा है। यह न केवल करोड़ों लोगों को जोड़ती है, बल्कि विविध संस्कृतियों का संगम कर राष्ट्र की प्रगति को गति देती है। ऐसे में इसकी स्वच्छता और संरक्षा हमारी सामूहिक जिम्मेदारी बनती है। यह मान लेना गलत है कि सफाई केवल कर्मचारियों का दायित्व है। जब हम कूड़ा कूड़ेदान में डालते हैं, दीवारों को गंदा नहीं करते और स्टेशन व डिब्बों की स्वच्छता बनाए रखने में योगदान देते हैं, तब हम सचमुच जिम्मेदार नागरिक साबित होते हैं। एक स्वच्छ स्टेशन और साफ-सुथरी ट्रेन यात्रियों को केवल सुखद अनुभव ही नहीं देती, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी हमारे देश की सकारात्मक छवि प्रस्तुत करती है। यह बताती है कि हम अपने संसाधनों और सार्वजनिक संपत्तियों का कितना सम्मान करते हैं।

बिहार के रेलवे बजट में ऐतिहासिक उछाल, 11 वर्षों में 9 गुना बढ़ोतरी

सूत्र/रे.स.ब्यू- केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण और इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 23 जुलाई, 2025 को लोकसभा में बिहार में रेलवे के तहत हो रहे विकास कार्यों की विस्तृत जानकारी साझा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार को रेलवे क्षेत्र में ऐतिहासिक लाभ प्राप्त हुआ है। उन्होंने बताया की बिहार में 11 वर्ष पूर्व राज्य के लिए रेलवे बजट मात्र Rs.1132 करोड़ था, उसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बढ़ाकर Rs.10,000 करोड़ कर दिया है। यह नौ गुना वृद्धि बिहार की आकांक्षाओं और जरूरतों के प्रति केंद्र सरकार की गहन प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा, ''आखिरकार, इन परियोजनाओं की शुरुआत भी एनडीए सरकार ने की थी और समापन भी एनडीए सरकार ने किया है। इससे स्पष्ट है कि बिहार की जनता के साथ न्याय केवल एनडीए ही कर सकती है।''

शिवहर-सीतामढ़ी रेलवे प्रोजेक्ट को मिली नई गति- लोकसभा में चर्चा के दौरान शिवहर सीतामढ़ी परियोजना पर बोलते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। बागमती नदी पर बनने वाला पुल, जो देकुली धाम शिवहर को जोड़ेगा, उसके लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इस परियोजना के भूमि अधिग्रहण के लिए 262 करोड़ की राशि पहले ही जमा कर दी गई है और कार्य तेजी से प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त, सीतामढ़ी शिवहर नई रेल लाइन परियोजना के लिए 557 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं, और उसका कार्य भी तीव्र गति से चल रहा है।

अमृत भारत ट्रेनों की सौगात- श्री वैष्णव ने यह भी कहा कि बिहार के विभिन्न क्षेत्रों को नई अमृत भारत ट्रेनों से जोड़ा गया है, जो पटना से दिल्ली, दरभंगा से दिल्ली, और दरभंगा से बैंगलोर जैसे प्रमुख मार्गों पर शुरू की गई हैं। उन्होंने कहा की अमृत भारत ट्रेनें प्रधानमंत्री जी की एक दूरदर्शी योजना का हिस्सा हैं, जिनका उद्देश्य यह है कि गरीब से गरीब वर्ग को भी बेहतर और आधुनिक सुविधाओं से युक्त रेल सेवा उपलब्ध कराई जा सके।

78 प्रतिशत से अधिक रेलवे पटरियों को 110 किलोमीटर प्रति घंटे और उससे अधिक की सेक्शनल गति के लिए उन्नत किया गया

सूत्र/रे.स.ब्यू- पिछले 10 वर्षों में भारतीय रेलवे ने गति क्षमता बढ़ाने के लिए रेल पटरियों का बड़े पैमाने पर उन्नयन और सुधार किया है। इसमें 60 किलोग्राम की पटरियों का उपयोग, चौड़े बेस वाले कंक्रीट स्लीपर, मोटे वेब स्विच, लंबे रेल पैनल, एच बीम स्लीपर, आधुनिक ट्रैक नवीनीकरण और रखरखाव मशीनों जैसी उन्नत तकनीकों का समावेश किया गया है। इन सुधारों के परिणामस्वरूप पटरियों की गति क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2014 में 110 किलोमीटर प्रति घंटा से कम गति वाले ट्रैक 47,897 किलोमीटर (60.4 प्रतिशत) थे, जो 2025 में घटकर 22,862 किलोमीटर (21.6 प्रतिशत) रह गए। 110 से 130 किलोमीटर प्रति घंटा की गति क्षमता वाले ट्रैक 26,409 किलोमीटर (33.3 प्रतिशत) से बढ़कर 59,800 किलोमीटर (56.6 प्रतिशत) हो गए। 130 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे अधिक की गति क्षमता वाले ट्रैक 5,036 किलोमीटर (6.3 प्रतिशत) से बढ़कर 23,010 किलोमीटर (21.8 प्रतिशत) हो गए। कुल ट्रैक लंबाई 79,342 किलोमीटर से बढ़कर 1,05,672 किलोमीटर हो गई। वंदे भारत रेलगाड़ियाँ- वर्तमान में भारतीय रेल नेटवर्क पर चल रही वंदे भारत रेलगाड़ियाँ अर्ध-उच्च गति वाली हैं, जिनकी डिजाइन गति 180 किलोमीटर प्रति घंटा और अधिकतम परिचालन गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। इनकी औसत गति ट्रैक की ज्यामिति, मार्ग में ठहराव तथा सेक्शन में रखरखाव कार्य जैसे कारकों पर निर्भर करती है। वंदे भारत स्लीपर संस्करण- वंदे भारत स्लीपर रेलगाड़ी का पहला प्रोटोटाइप तैयार हो चुका है। व्यापक क्षेत्रीय परीक्षणों से प्राप्त अनुभव के आधार पर इसका पहला रैक संचालन के लिए चालू किया जा रहा है। यह जानकारी केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

लॉजिस्टिक्स सेवाएं जितनी मजबूत होंगी, देश की सीमाएं भी उतनी ही मजबूत होंगी: रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह

सूत्र/रे.स.ब्यू- गति शक्ति विश्वविद्यालय का तीसरा दीक्षांत समारोह वडोदरा में आयोजित हुआ, जिसमें रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह वर्चुअल माध्यम से मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने कहा कि भारत बुनियादी ढांचे और लॉजिस्टिक्स क्षेत्रों में अभूतपूर्व परिवर्तन का साक्षी है, जो आर्थिक विकास की मजबूत नींव रख रहा है। लॉजिस्टिक्स को 21वीं सदी के भारत के लिए "गेम चेंजर" बताते हुए उन्होंने युवाओं से विकसित भारत के निर्माण में जिम्मेदारी निभाने का आह्वान किया। श्री सिंह ने कहा कि मजबूत लॉजिस्टिक्स सेवाएं सीमाओं की सुरक्षा से जुड़ी हैं। रक्षा उत्पादों और सैनिकों के लिए आपूर्ति समय पर सीमा तक पहुँचने से सीमा रक्षकों का मनोबल बढ़ता है। उन्होंने बताया कि मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट हब निर्माण और मिशन मोड योजनाओं से लॉजिस्टिक्स लागत में कमी और डेटा-आधारित निर्णय में वृद्धि हुई है। केंद्रीय रेल मंत्री व कुलाधिपति श्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पिछले 11 वर्षों में भारतीय रेलवे में बड़े बदलाव हुए हैं। पिछले एक वर्ष में 5,300 किमी रेल नेटवर्क विस्तार और 368 किमी सुरंग निर्माण हुआ है। उन्होंने कहा कि इतिहास में ढाई सदियों को छोड़कर भारत हमेशा शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में रहा है और गति शक्ति विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों से मानव संसाधन निर्माण द्वारा यह स्थान पुनः प्राप्त किया जा सकता है। विश्वविद्यालय ने 40 औद्योगिक व शैक्षणिक संस्थानों के साथ एमओयू किए हैं और मरीन इंजीनियरिंग शोध पर जोर दिया है। समारोह में 194 विद्यार्थियों को डिग्री, शैक्षणिक उत्कृष्टता पुरस्कार, उत्कृष्ट परियोजना और सर्वश्रेष्ठ छात्र पुरस्कार दिए गए। कुलपति प्रो. (डॉ.) मनोज चौधरी ने स्वागत भाषण दिया। सांसद डॉ. हेमांग जोशी, राजमाता शुभांगिनी राजे गायकवाड़, भारतीय सेना व रेलवे अधिकारी, छात्र व अभिभावक उपस्थित थे। गति शक्ति विश्वविद्यालय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विजन का हिस्सा है, जो पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान से जुड़ा है। इसका उद्देश्य एकीकृत, कुशल बुनियादी ढांचा पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है, जिसमें 16 मंत्रालय एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मिलकर कार्य करते हैं।

पाठको से अनुरोध

आपको यह अंक कैसा लगा? इसमें आप और क्या परिवर्तन चाहते हैं? कृपया अपने सुझावों से अवश्य ही अवगत कराएं जिससे हम पत्रिका में सुधार कर सकें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा।

प्रधान संपादक

मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के यात्रियों को मिली सीधी कनेक्टिविटी।

सूत्र/रे.स.ब्यू- 03 अगस्त 2025 को माननीय केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने पश्चिम रेलवे के भावनगर रेलवे स्टेशन से एक साथ तीन नई ट्रेनों की सौगात दी। भावनगर टर्मिनस से अयोध्या एक्सप्रेस, रीवा से पुणे (हड़पसर) साप्ताहिक सुपरफास्ट एवं जबलपुर से रायपुर इंटरसिटी नई एक्सप्रेस रेल सेवाओं को माननीय रेल मंत्री द्वारा हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय, गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल सहित राज्यों के माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, अन्य गणमान्य नागरिक तथा आमजन भी जुड़कर सहभागी बने। इस अवसर पर केंद्रीय रेल मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रेलवे के क्षेत्र में ऐतिहासिक प्रगति हुई है। रेलवे में इंफ्रास्ट्रक्चर को गति प्रदान करते हुए तेजी से कार्य निष्पादित हो रहे हैं, जिससे प्रदेशों में अभूतपूर्व विकास हो रहा है। वर्तमान में रेलवे द्वारा यात्री सुविधाओं को विस्तारित करते हुए नई तकनीकी ट्रेनें जैसे वंदे भारत, अमृत भारत, नमो भारत ट्रेनों को चलाया जा रहा है। उन्होंने अपने उद्‌बोधन में कहा कि आगामी सितंबर माह से वंदे भारत स्लीपर ट्रेन भी चलाई जाएंगी, और साथ ही बहुत जल्द अहमदाबाद से मुंबई बुलेट ट्रेन की भी सौगात मिलेगी। श्री वैष्णव ने बताया कि मध्य प्रदेश में कई महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि रीवा-पुणे ट्रेन रीवा, सतना, मैहर, कटनी, जबलपुर, नैनपुर, बालाघाट सहित मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों, जहाँ से बड़ी संख्या में लोग पुणे (महाराष्ट्र) की ओर यात्रा करते हैं, के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी। इसी प्रकार जबलपुर-रायपुर ट्रेन भी जबलपुर, नैनपुर, बालाघाट, गोंदिया सहित मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के यात्रियों के लिए लाभकारी होगी, जहाँ से बड़ी संख्या में लोग रायपुर (छत्तीसगढ़) की ओर यात्रा करते हैं। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश के विंध्य एवं महाकौशल की जनता को महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़ के लिए सीधे कनेक्टिविटी हो जाने से औद्योगिक, शैक्षणिक एवं पर्यटन को बढ़ावा तथा प्रदेश के विकास को गति मिलेगी।

नई ट्रेन गाड़ी संख्या 01702 जबलपुर - रायपुर उद्‌घाटन शुभारंभ समारोह :

जबलपुर रेलवे स्टेशन भी ट्रेन उद्‌घाटन समारोह का साक्षी बना। इस कार्यक्रम के दौरान जबलपुर रेलवे स्टेशन से माननीय लोक निर्माण मंत्री मध्य प्रदेश शासन श्री राकेश सिंह, माननीय सांसद राज्यसभा श्रीमती सुमित्र बाल्मिक, माननीय सांसद श्री आशीष दुबे, माननीय विधायक कैंट श्री अशोक रोहाणी, माननीय विधायक पाटन श्री अजय विश्नोई, माननीय विधायक उत्तर डॉ. अभिलाष पांडेय, माननीय महापौर श्री जगत बहादुर सिंह, शहर के प्रतिष्ठित जनप्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित हुए। रेल प्रशासन की ओर से महाप्रबंधक श्रीमती शोभना बंदोपाध्याय, अपर महाप्रबंधक श्री प्रमोद कुमार खत्री, प्रमुख मुख्य परिचालन प्रबंधक श्री कुशाल सिंह, प्रमुख मुख्य वाणिज्य प्रबंधक श्री मनीष तिवारी, प्रमुख मुख्य सुरक्षा आयुक्त श्री राजीव कुमार यादव एवं मंडल रेल प्रबंधक श्री कमल कुमार तलरेजा सहित अन्य रेल अधिकारी एवं कर्मचारियों ने कार्यक्रम को सफल बनाया।

नई ट्रेन गाड़ी संख्या 02152 रीवा -हड़पसर उद्‌घाटन शुभारंभ समारोह :

इसी प्रकार रीवा रेलवे स्टेशन से माननीय उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश श्री राजेंद्र शुक्ल, माननीय सांसद श्री जनार्दन मिश्रा, शहर के गणमान्य नागरिक तथा बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे। सतना रेलवे स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में माननीय सांसद श्री गणेश सिंह, गणमान्य नागरिक एवं बड़ी संख्या में आमजन शामिल हुए।

रीवा-हड़पसर (पुणे)-रीवा साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन की नियमित सेवा :

गाड़ी संख्या 20152 रीवा-हड़पसर (पुणे) साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन प्रत्येक बुधवार सुबह 06:45 बजे रीवा से प्रस्थान करेगी और सतना, मैहर, कटनी, जबलपुर, नैनपुर, बालाघाट, गोंदिया, नागपुर, वर्धा, बडनेरा, अकोला, भुसावल, जलगांव, मनमाड, कोपरगांव, अहमदनगर, दौड़ कॉर्ड लाइन होते हुए गुरुवार सुबह 09:45 बजे हड़पसर (पुणे) पहुंचेगी।

वापसी में गाड़ी संख्या 20151 हड़पसर (पुणे)-रीवा साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस प्रत्येक गुरुवार दोपहर 15:15 बजे पुणे से प्रस्थान करेगी और दौड़ कॉर्ड लाइन, अहमदनगर, कोपरगांव, मनमाड, जलगांव, भुसावल, अकोला, बडनेरा, वर्धा, नागपुर, गोंदिया, बालाघाट, नैनपुर, जबलपुर, कटनी, मैहर, सतना होते हुए शुक्रवार शाम 17:30 बजे रीवा पहुंचेगी। इस साप्ताहिक ट्रेन में कुल 20 एलएचबी कोच होंगे, जिनमें चार सेकंड सिटिंग, तीन तृतीय वातानुकूलित, तीन तृतीय वातानुकूलित इकोनॉमी, दो द्वितीय वातानुकूलित तथा शेष स्लीपर श्रेणी के कोच होंगे।

जबलपुर-रायपुर-जबलपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन की नियमित सेवा :

गाड़ी संख्या 11702 जबलपुर-रायपुर एक्सप्रेस ट्रेन प्रतिदिन सुबह 06:00 बजे जबलपुर से प्रस्थान करेगी और मदनमहल, नैनपुर, बालाघाट, गोंदिया, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, दुर्ग होते हुए उसी दिन दोपहर 13:50 बजे रायपुर पहुंचेगी। वापसी में गाड़ी संख्या 11701 रायपुर-जबलपुर एक्सप्रेस ट्रेन प्रतिदिन दोपहर 14:45 बजे रायपुर से प्रस्थान करेगी और दुर्ग, राजनांदगांव, डोंगरगढ़, गोंदिया, बालाघाट, नैनपुर, मदनमहल होते हुए उसी दिन रात 22:45 बजे जबलपुर पहुंचेगी। इस ट्रेन में कुल 15 एलएचबी कोच होंगे, जिनमें आठ जनरल सिटिंग, चार द्वितीय चेयरकार तथा एक वातानुकूलित चेयरकार कोच शामिल है।

रेलवे स्टेशनों पर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र परियोजना

रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों सहित आम जनता को गुणवत्तापूर्ण और किफायती दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना इसका लक्ष्य

सूत्र/रे.स.ब्यू- केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र परियोजना स्कीम के अंतर्गत, रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों सहित आम जनता को गुणवत्तापूर्ण, किफायती दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 30 जून, 2025 तक देश भर के रेलवे स्टेशनों पर कुल 106 जन औषधि केंद्र (जेएके) खोले गए हैं। देश भर में 30 जून, 2025 तक कुल 16,912 कृषि ऋण केंद्र (जेएके) खोले जा चुके हैं, जिनमें से 8,660 ग्रामीण क्षेत्रों में खोले गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच बढ़ाने के लिए इस योजना के तहत प्राथमिक कृषि ऋण समितियों और अन्य सहकारी समितियों द्वारा जेएके खोलने के लिए सहकारिता मंत्रालय के साथ साझेदारी की गई है। औसतन, लगभग 10 से 12 लाख लोग प्रतिदिन इन केंद्रों पर आते हैं और ग्रामीण एवं सुदूर क्षेत्रों सहित पूरे देश में किफायती दामों पर गुणवत्तापूर्ण दवाइयां प्राप्त करते हैं। इस योजना के परिणामस्वरूप, पिछले 11 वर्षों में, ग्रामीण एवं सुदूर क्षेत्रों सहित पूरे देश में नागरिकों को ब्रांडेड दवाओं की कीमतों की तुलना में लगभग 38,000 करोड़ रूपये की अनुमानित बचत हुई है। ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों सहित देश भर के जेएके में सुचारू आपूर्ति और उत्पाद उपलब्धता के लिए, एक संपूर्ण आईटी-सक्षम आपूर्ति श्रृंखला प्रणाली स्थापित की गई है, जिसमें एक केंद्रीय वेयरहाउस, चार क्षेत्रीय वेयरहाउस और 39 वितरक नियुक्त हैं। इसके अतिरिक्त 400 फास्ट-मूविंग जनऔषधि उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उनकी नियमित निगरानी की जाती है। इसके अतिरिक्त, 200 जन औषधि उत्पादों के लिए एक न्यूनतम भंडारण अधिदेश लागू किया गया है, जिसमें स्कीम प्रोडक्ट बास्केट में सबसे अधिक बिकने वाले 100 जनऔषधि उत्पाद और बाजार में तेजी से बिकने वाले 100 जनऔषधि उत्पाद शामिल हैं। भंडारण अधिदेश के तहत, जेएके मालिक अपने द्वारा रखरखाव किए गए उक्त 200 उत्पादों के स्टॉक के आधार पर प्रोत्साहन प्राप्त करने के दावेदार बन जाते हैं।

समस्त प्रकार के कानूनी मामलों का न्यायिक क्षेत्र प्रयागराज होगा

सम्पादक, प्रकाशक, मुद्रक एवं स्वामी ज्ञानेन्द्र कुमार श्रीवास्तव दि. इलाहाबाद ब्लॉक वर्क्स प्रा. लि. 329/255 चक. जीरो रोड इलाहाबाद से मुद्रित एवं 502 पंचशीला भवन त्रिवेनी रोड, नेतानगर, कीडगंज प्रयागराज-211003 से प्रकाशित।
आर.एन. आई नं. 51097-90
पोस्ट ए.डी.-8
मो. 9773946044 / 9793956044
फोन नं. 0532-2418040

पाठकों से अनुरोध

विगत वर्षों की भाँति आगामी वर्ष के लिए अपनी रेल समाचार ब्यूरो पत्रिका को सुरक्षित करने के लिए वार्षिक सद्स्यता शुल्क शीघ्र भेजने की कृपा करें, जिससे उक्त पत्रिका आपको नियमित भेजी जा सके।

सहयोग राशि:

१. उच्चतम अधिकारी-5000 रु. मात्र
२. उच्च अधिकारी- 3500 रु. मात्र
३. अधीनस्थ अधिकारी-2500 रु. मात्र
४. रेलकर्मी/अन्य सदस्य-1000 रु. मात्र

सम्पादक, प्रकाशक, मुद्रक एवं स्वामी ज्ञानेन्द्र कुमार श्रीवास्तव
पंजिकृत कार्यालय
502 पंचशीला भवन त्रिवेनी रोड, नेतानगर, कीडगंज प्रयागराज-211003 से प्रकाशित।
कैंप कार्यालय- अनिल केन (रिर्पोटर) कार्यालय 8439 आर्य नगर पहाड़गंज दिल्ली-55

केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने नासिक-त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ 2027 रेल योजनाओं की समीक्षा की।

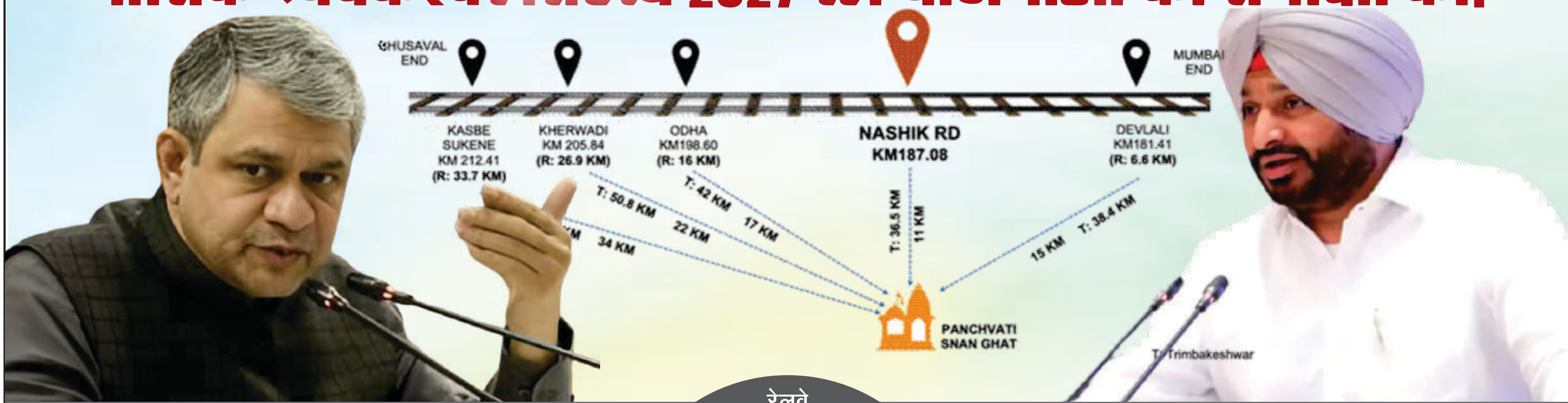

सूत्र/रे.स.ब्यू- रेल मंत्रालय ने प्रयागराज महाकुंभ की तरह ही 2027 में आयोजित होने वाले नासिक-त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ के लिए अग्रिम तैयारियां आरंभ कर दी हैं। केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव और राज्य मंत्री श्री रवनीत सिंह बिट्टू ने योजनाओं की गहन समीक्षा की। मध्य रेलवे के जीएम, भुसावल डिवीजन के डीआरएम और अन्य अधिकारियों ने मंत्रियों तथा रेलवे बोर्ड को इसकी योजना और कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में जानकारी दी।

मेला क्षेत्र से संपर्क सुदृढ़ बनाना : रेलवे सिंहस्थ के लिए व्यापक बुनियादी ढांचे और प्रचालनगत उन्नयन का कार्य आरंभ करेगा। इसने पूरे क्षेत्र में स्टेशनों की क्षमता विस्तार के लिए एक एकीकृत योजना तैयार की है। इसका लक्ष्य नासिक सिंहस्थ 2027 के दौरान यात्रियों की सुगम आवाजाही सुनिश्चित करना है। रेल मंत्री ने अधिकारियों से महाकुंभ 2025 के अनुभव से प्राप्त सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों को अपनाने का आग्रह किया। उन्होंने अधिकारियों को नासिक के सभी निकटवर्ती स्टेशनों पर पर्याप्त सुविधाएं विकसित करने की सलाह दी। उन्होंने निर्बाध परिवहन के लिए पर्याप्त स्टेब्लिंग क्षमता की आवश्यकता पर बल दिया। अधिकारियों ने बताया कि मेला क्षेत्र के आसपास के 5 प्रमुख स्टेशनों पर यात्री यातायात का प्रबंधन किया जाएगा। ये स्टेशन हैं: नासिक रोड, देवलाली, ओढ़ा, खेरवाड़ी और कसबे सुकेणे।

बुनियादी ढांचे का उन्नयन, यात्री सुविधाओं में वृद्धि: रेलवे अधिकारियों ने चिन्हित पांचों स्टेशनों पर प्रस्तावित बुनियादी ढांचे के कार्यों और यात्री सुविधाओं का विवरण साझा किया। इन स्टेशनों पर नियोजित कार्यों की लागत 1,011 करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान है।

नासिक रोड: प्लेटफॉर्म-4 को दो दिशाओं वाला बनाया जाएगा। प्लेटफॉर्म-1 का विस्तार 24 कोच वाली ट्रेनों के लिए किया जाएगा। 12 मीटर चौड़ा एफओबी बनाया जाएगा। माल शेड को होल्डिंग एरिया के रूप में उपयोग करने का प्रस्ताव है। नासिक रोड पर स्टेब्लिंग लाइनें विकसित की जा रही हैं। प्लेटफॉर्म की सतह, चारदीवारी और मेला टावर का भी उन्नयन किया जाएगा।

> रेलवे अधिकारी राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ निरंतर संपर्क में हैं। रेलवे और महाराष्ट्र राज्य सरकार के बीच घनिष्ठ समन्वयन है। आने वाले महीनों में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस के साथ प्रगति की एक संयुक्त समीक्षा की जाएगी।

देवलाली: अतिरिक्त प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे। दो 6 मीटर चौड़े पैदल ऊपरी पुल (एफओबी) बनाए जाएंगे। उन्नत कोच और वैगन परीक्षण सुविधा केंद्रों (3 स्टेब्लिंग लाइन और 2 पिट लाइन के साथ) के निर्माण की भी योजना है। एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने का प्रस्ताव है।

ओधा: लूप लाइनों वाला एक आइलैंड प्लेटफॉर्म विकसित किया जाएगा। चार 6 मीटर चौड़े एफओबी बनाए जाएंगे। लंबी दूरी की लूप लाइन और यार्ड रीम डलिंग की भी योजना है। 5 स्टेब्लिंग लाइनें बनाने का प्रस्ताव है।

खेरवाड़ी: एक नया डाउन प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। दो 6 मीटर चौड़े पैदल ऊपरी पुल (एफओबी) बनाए जाएंगे। यार्ड रीमॉडलिंग का भी प्रस्ताव है।

कसबे-सुकेणे: प्लेटफार्मों का विस्तार किया जाएगा। दो 6 मीटर चौड़े पैदल ऊपरी पुल (एफओबी) बनाए जाएंगे। एक सामान्य डिस्पैच सुविधा केंद्र स्थापित किया जाएगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त, सभी पांचों स्टेशनों पर विभिन्न यात्री सुविधाओं के विकास की योजना है। इनमें कवर्ड ओवर प्लेटफॉर्म, पानी की टंकियां, नए शौचालय और वाटरप्रूफ होल्डिंग एरिया शामिल हैं। सर्कुलेटिंग एरिया, रास्ते, प्रवेश/निकास मार्ग और यात्री सूचना प्रणालियों को भी उन्नत करने की योजना है। रेलवे उपरोक्त कार्यों को 2 वर्षों की समय-सीमा के भीतर पूरा करने के लिए तत्पर है। कुल 65 प्रस्तावित कार्यों में से 33 के आकलनों को पहले ही स्वीकृत दी जा चुकी है।

सिंहस्थ के लिए विशेष रेलगाड़ियां: अनुमानित 3 करोड़ से अधिक तीर्थयात्रियों के आने की संभावना है, जो सिंहस्थ 2015 की तुलना में लगभग 50 गुना अधिक है। इसे ध्यान में रखते हुए, रेलवे बहुत अधिक संख्या में विशेष रेलगाड़ियां चलाने की योजना बना रहा है। देश भर से आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए लंबी दूरी की विशेष और छोटी दूरी की मेमू ट्रेनें उपलब्ध कराई जाएंगी। ये नासिक को कामाख्या, हावड़ा, पटना, दिल्ली, जयपुर, बीकानेर, मुंबई, पुणे, नागपुर और नांदेड़ जैसे महत्वपूर्ण स्टेशनों से जोड़ेंगी। एक राउंड-ट्रिप विशेष सर्किट ट्रेन भी चलाई जाएगी। यह तीन ज्योतिर्लिंगों- त्र्यंबकेश्वर, घृष्णेश्वर और ओंकारेश्वर को जोड़ेगी।

भीड़ का सुचारु रूप से प्रबंधन करना: तीर्थ यात्रियों की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक प्रमुख स्टेशन पर बड़े होल्डिंग एरिया विकसित किए जा रहे हैं। एक केंद्रीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। यह प्रभावी निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरों और पूर्वानुमानित समय-निर्धारण के लिए एआई उपकरणों से सुसज्जित होगा।

Tamil Nadu Gets a Major Infrastructure Boost with New Rail, Road, Port, Airport & Power Projects.

Source/RSB- Shri Narendra Modi, Hon'ble Prime Minister of India, who was on a two-day visit to Tamil Nadu, inaugurated and dedicated projects implemented by various ministries such as Railways, Roadways, Ports, Airport and Power at a function held in Tuticorin on 26th July 2025. This includes key railway electrification and doubling projects costing Rs. 1030 Crores. Shri R.N. Ravi, Hon'ble Governor of Tamil Nadu, Shri Kinjarapu Rammohan Naidu, Hon'ble Union Minister of Civil Aviation, Dr. L. Murugan, Hon'ble Minister of State for Information & Broadcasting and Parliamentary Affairs, Shri Thangam Thennarasu, Hon'ble Minister of Finance, Tamil Nadu, Dr. T.R.B. Rajaa, Minister for Industries, Investment Promotion and Commerce, Tamil Nadu, Smt. P. Geetha Jeevan, Hon'ble Minister of Social Welfare and Women Empowerment, Tamil Nadu, Shri Anitha R. Radhakrishnan, Minister for Fisheries, Fishermen Welfare, and Animal Husbandry, Shri Kanimozhi Karunanidhi, Hon'ble Member of Parliament & Shri Nainar Nagenthran, Hon'ble MLA participated in the event.

A Massive Push for Rail Infra in Tamil Nadu

PM dedicated three important railway projects costing Rs. 1030 Crores benefiting the state of Tamil Nadu. These projects will strengthen rail

connectivity in the southern districts of Tamil Nadu covering Tirunelveli, Kanniyakumari, Madurai and Theni districts and boost the economic progress of the region. Moreover, the projects will enhance the efficiency of train operations easing both passenger and freight traffic. The projects dedicated by Hon'ble Prime Minister are detailed below:

1. Dedication to the Nation of Madurai - Bodinayakkanur Rail Line Electrification (90 KM)

This eco-friendly and sustainable railway project completed at a cost of Rs. 99

Crore, significantly enhances rail connectivity for the people of Madurai and Theni districts, paving the way for faster and more efficient travel. The project is expected to increase tourist footfall to scenic destinations such as Theni and Bodi. Moreover, it brings tangible benefits to farmers, small vendors, students, and daily commuters by providing them with better and more reliable travel options.

2. Dedication to the Nation - Doubling of Nagercoil Town - Nagercoil Jn - Kanniyakumari Railway Line (21 KM)

Completed at a cost of Rs. 650 Crore, this project is a part of the Thiruvananthapuram–Kanniyakumari Railway Line Doubling Project and aimed at strengthening rail connectivity between Tamil Nadu and Kerala. By enhancing regional economic integration, it facilitates smoother movement for daily commuters, tourists, and businesses. The project supports agricultural and manufacturing sectors by improving the transport of goods to coastal regions, thereby boosting trade and local economies. It also enhances the reliability and frequency of train services, offering significant benefits to students, vendors, traders, and regular passengers. Additionally, it provides greater convenience for tourists visiting iconic landmarks and scenic locations in Kanyakumari and Thiruvananthapuram.

3. Dedication to the Nation of Doubling of Aralvaymozhi - Nagercoil Jn (12.87 KM) & Tirunelveli - Melappalayam (3.6 KM) Railway Lines

This project, completed at a cost of Rs. 283 Crore, is part of the Vanchi Maniyachchi–Nagercoil Railway Line Doubling project. It fulfills the demand for both passenger and freight traffic in South Tamil Nadu. It will significantly reduce travel time between major routes such as Chennai–Nagercoil and Chennai–Kanniyakumari, enhancing overall connectivity across the region. It supports regional economic growth by improving logistics and transportation efficiency for local industries, thereby contributing to the overall development of the area.

79वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर भारतीय रेल ने बड़े उत्साह और उल्लास के साथ "हर घर तिरंगा" अभियान में भाग लिया

"हर घर तिरंगा" अभियान में रेलवे कर्मचारियों की व्यापक भागीदारी रही

सूत्र/रे.स.ब्यू- 79वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री सतीश कुमार, रेलवे बोर्ड के सदस्य, रेलवे बोर्ड के सचिव और रेलवे बोर्ड के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी रेल भवन में आयोजित 'हर घर तिरंगा' कार्यक्रम में राष्ट्रीय ध्वज के साथ शामिल हुए। रेलवे कर्मचारियों के बीच राष्ट्रीय ध्वज वितरित किया गया। 'हर घर तिरंगा' अभियान में रेलवे कर्मचारियों की व्यापक भागीदारी देखी गई।'हर घर तिरंगा' अभियान आजादी के अमृत महोत्सव के तत्वावधान में शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य नागरिकों को भारत की स्वतंत्रता के उपलक्ष्य में तिरंगा घर लाने और उसे फहराने के लिए प्रोत्साहित करना है। यह पहल इस विचार से उत्पन्न हुई है कि राष्ट्रीय ध्वज के साथ हमारा जुड़ाव पारंपरिक रूप से व्यक्तिगत न होकर औपचारिक और संस्थागत रहा है। ध्वज को घर लाना तिरंगे के साथ व्यक्तिगत जुड़ाव का एक प्रतीकात्मक कार्य है और राष्ट्र निर्माण के प्रति हमारी साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस अभियान का उद्देश्य लोगों में देशभक्ति की भावना जगाना और भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। भारतीय रेल ने 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में बड़े उत्साह और उल्लास के साथ भाग लिया। प्रमुख रेलवे स्टेशनों, कार्यालयों, भवनों और आवासीय कॉलोनियों को राष्ट्रीय ध्वज से सुसज्जित किया गया और तिरंगे की रोशनी से जगमगाया गया। स्टेशन भवनों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है और प्रतिष्ठित रेलवे पुलों पर गर्व के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराकर देशभक्ति की भावना को और बढ़ाया गया है।

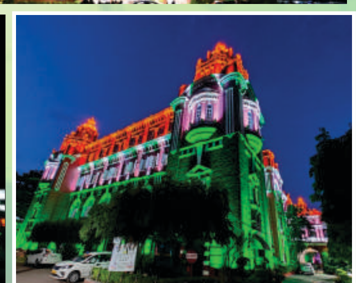

देशभर के रेलवे परिसरों में स्वतंत्रता दिवस गर्व और सम्मान के साथ मनाया गया। ध्वजारोहण के बाद, रेलकर्मियों ने राष्ट्र की प्रगति में अपने योगदान को जारी रखने की शपथ ली।

पूर्व रेलवे मुख्यालय, फेयरली प्लेस में 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक श्री मिलिंद देवस्कर ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर सलामी दी।

स्वतंत्रता दिवस के गौरवपूर्ण अवसर पर दक्षिण रेलवे के महाप्रबंधक श्री आर. एन. सिंह ने पेरम्बूर रेलवे स्टेडियम में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की भावना और देशभक्ति का सम्मान करते हुए एकता और राष्ट्रगौरव का संदेश दिया।

पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (NFR) के महाप्रबंधक श्री चेतन कुमार श्रीवास्तव ने 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह पर मालिगांव स्थित NFRSA इंडोर स्टेडियम में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर उन्होंने उत्कृष्ट बहादुरी और कर्तव्यों के प्रति समर्पण दिखाने वाले चयनित रेलकर्मियों को 'कर्मवीर पुरस्कार' प्रदान कर सम्मानित किया।

मध्य रेलवे के महाप्रबंधक श्री धर्मवीर मीणा ने मुंबई स्थित ऐतिहासिक छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) हेरिटेज भवन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया।

दक्षिण पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक मुकुल सरन माथुर ने हुब्बली स्थित रेल सौधा में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर अधिकारियों, कर्मचारियों और उनके परिवारजनों ने देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रमों में भाग लिया।

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मुख्यालय में गरिमामयी समारोह आयोजित किया गया, जिसमें महाप्रबंधक श्री तरुण प्रकाश जी ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली।

श्री अमिताभ, महाप्रबंधक, उत्तर पश्चिम रेलवे ने उत्तर पश्चिम रेलवे मुख्यालय, जयपुर में आयोजित समारोह में ध्वजारोहण किया।

महाप्रबंधक, पश्चिम रेलवे, श्री विवेक कुमार गुप्ता ने मुख्यालय में आयोजित समारोह में ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी तथा रेल सुरक्षा बल की परेड का निरीक्षण किया।

उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक श्री अशोक कुमार वर्मा ने प्रधान कार्यालय, बड़ौदा हाउस में ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर उन्होंने राष्ट्रध्वज को सलामी दी और उपस्थित सभी अधिकारियों, कर्मचारियों तथा अतिथियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ प्रेषित कीं।

महाप्रबंधक श्री परमेश्वर फुंकवाल ने भुवनेश्वर स्टेडियम में राष्ट्रीय ध्वज फहराया तथा अपने उद्बोधन में पूर्व तट रेलवे की वर्षभर की उल्लेखनीय उपलब्धियों पर प्रकाश डाला।

दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक श्री अनिल कुमार मिश्रा ने कोलकाता के गार्डन रीच स्थित मुख्यालय में ध्वजारोहण किया।

महाप्रबंधक श्री छत्रसाल सिंह ने हाजीपुर स्थित महाप्रबंधक कार्यालय 'रेल निकेतन' परिसर में ध्वजारोहण किया एवं राष्ट्रध्वज को सलामी दी।

79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उत्तर मध्य रेलवे मुख्यालय, प्रयागराज में आयोजित समारोह में महाप्रबंधक उपेन्द्र चन्द्र जोशी द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर उन्होंने उपस्थित अधिकारियों, कर्मचारियों एवं अतिथियों को संबोधित करते हुए स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएँ दीं और देश एवं रेल संगठन के प्रति निष्ठा और समर्पण के महत्व पर प्रकाश डाला।

दक्षिण मध्य रेलवे के महाप्रबंधक श्री संजय कुमार श्रीवास्तव ने सिकंदराबाद स्थित रेलवे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स (RSC) में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर उन्होंने उपस्थित अधिकारियों, कर्मचारियों एवं अतिथियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएँ दीं ।

महाप्रबंधक,पूर्वोत्तर रेलवे सुश्री सौम्या माथुर ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम, गोरखपुर में ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर उन्होंने राष्ट्रध्वज को सलामी दी तथा रेलवे सुरक्षा बल तथा अन्य द्वारा प्रस्तुत परेड का निरीक्षण किया।

आयुष मंत्रालय के राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड ने औषधीय पौधों के संरक्षण और जन जागरूकता बढ़ाने के लिए दो अहम समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

सूत्र/रे.स.ब्यू- आयुष मंत्रालय के राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी) ने औषधीय पौध संरक्षण व जनजागरूकता के लिए दो अहम समझौता ज्ञापन (एमओयू) किए। समारोह का आयोजन निर्माण भवन में हुआ, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) व स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री प्रतापराव जाधव ने की। पहला एमओयू एनएमपीबी और ईश वेद-बायोप्लांट्स वेंचर, पुणे, महाराष्ट्र के बीच हुआ, जिसका उद्देश्य ऊतक संवर्धन विधियों से दुर्लभ, लुप्तप्राय एवं संकटग्रस्त औषधीय पौधों के जर्मप्लाज्म का संरक्षण व रखरखाव है। इससे आयुष उद्योग में इन पौधों की सतत आपूर्ति, व्यापक खेती और हितधारकों को बेहतर मूल्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी। दोनों पक्ष औषधीय पादप क्षेत्र और आयुष उद्योग के विकास हेतु सहयोग क्षेत्रों की पहचान करेंगे। दूसरा त्रिपक्षीय एमओयू एनएमपीबी, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (AIIA) और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS), नई दिल्ली के बीच हुआ। इसके तहत AIIMS परिसर में AIIA द्वारा राष्ट्रीय औषधीय पौध उद्यान स्थापित होगा, जो औषधीय पौधों के प्रति जनजागरूकता फैलाएगा। दूरदराज से आने वाले मरीज, छात्र व अस्पताल आगंतुक प्रत्यक्ष लाभान्वित होंगे। अपने संबोधन में श्री जाधव ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक स्वस्थ और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को रेखांकित करते हुए कहा कि पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक विज्ञान से जोड़कर यह लक्ष्य साकार किया जा रहा है। उन्होंने इन एमओयू को भारत की औषधीय पादप विरासत संरक्षण व संवर्धन में मील का पत्थर बताया। ये समझौते औषधीय पौधों के क्षेत्र में साक्ष्य-आधारित संरक्षण, अनुसंधान और जनभागीदारी को प्रोत्साहित करने में आयुष मंत्रालय के निरंतर प्रयासों की महत्वपूर्ण उपलब्धि हैं।

आयुष मंत्रालय शीर्ष अनुसंधान परिषदों के माध्यम से वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रोत्साहित कर रहा है

सूत्र/रे.स.ब्यू- आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेदीय (CCRAS), यूनानी (CCRUM), होम्योपैथी (CCRH), सिद्ध (CCRS) और योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा (CCRYN) के लिए स्वतंत्र शीर्ष अनुसंधान परिषदें स्थापित की हैं। इनकी गतिविधियां नैदानिक अनुसंधान, औषधीय पादप अनुसंधान, औषध मानकीकरण, फार्माकोल जिकल अध्ययन और साहित्यिक प्रलेखन पर केंद्रित हैं। साथ ही ओपीडी, आईपीडी सेवाएं, वृद्धावस्था स्वास्थ्य क्लीनिक, टीएचसीआरपी, स्वास्थ्य रक्षण और मोबाइल स्वास्थ्य कार्यक्रम भी संचालित हैं। मंत्रालय "आयुर्ज्ञान" योजना के तहत अनुसंधान, नवाचार और विकास के लिए शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं चिकित्सा संस्थानों को वित्तीय सहायता देता है।

पिछले तीन वर्षों में प्रकाशित और पूर्ण हुए अध्ययनों की संख्या इस प्रकार हैं

- CCRAS: 189 पूर्ण, 522 प्रकाशित
- CCRUM: 104 पूर्ण, 484 प्रकाशित
- CCRH:184 पूर्ण, 88 प्रकाशित
- CCRS: 32 पूर्ण, 195 प्रकाशित
- CCRYN: 63 पूर्ण व प्रकाशित

ICMR और CCRAS ने AIIMS दिल्ली, जोधपुर, नागपुर और ऋषिकेश में "आयुष ICMR उन्नत एकीकृत स्वास्थ्य अनुसंधान केंद्र" (AI-AC-IHR) स्थापित किए हैं, जो क्रमशः गैस्ट्रो-इंटेस्टाइनल विकार, महिला एवं बाल स्वास्थ्य, वृद्धावस्था स्वास्थ्य और कैंसर देखभाल पर केंद्रित हैं। CCRUM ने AIIMS, जामिया मिलिया इस्लामिया, NIPER, अन्ना विश्वविद्यालय सहित कई संस्थानों के साथ MOU किए हैं। CCRS नई दिल्ली में कैंसर हेतु एकीकृत सिद्ध OPD चला रहा है। CCRH, AIIMS दिल्ली, AIIMS झज्जर और अन्य अस्पतालों में होम्योपैथी को मुख्यधारा स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ रहा है, जिसमें सफदरजंग अस्पताल, लेडी हार्डिंग कॉलेज, दिल्ली छावनी अस्पताल, BRD मेडिकल कॉलेज गोरखपुर, सिविल अस्पताल आइजोल और जिला अस्पताल दीमापुर में सेवाएं दी जा रही हैं। राज्यसभा में केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री प्रतापराव जाधव ने यह जानकारी दी।

आयुष मंत्रालय के परामर्श से एफएस-एसएआई ने श्रेणी 'ए' के अंतर्गत आयुर्वेद आहार उत्पादों की सुस्पष्ट सूची जारी की

सूत्र/रे.स.ब्यू- भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने आयुष मंत्रालय के परामर्श से "आयुर्वेद आहार" श्रेणी के अंतर्गत श्रेणी 'ए' उत्पादों की सुस्पष्ट सूची जारी की। यह कदम 2022 में लागू खाद्य सुरक्षा एवं मानक (आयुर्वेद आहार) विनियम के तहत, अनुसूची 'ए' में सूचीबद्ध प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथों पर आधारित व्यंजनों की प्रामाणिकता सुनिश्चित करता है। यह सूची अनुसूची बी के नोट (1) के अंतर्गत जारी हुई है और खाद्य व्यवसाय संचालकों (एफबीओ) को निर्माण के लिए स्पष्ट संदर्भ देती है। भविष्य में उत्पाद जोड़ने हेतु एफबीओ, अनुसूची 'ए' में दिए ग्रंथों से प्रमाण सहित अनुरोध कर सकेंगे। अद्यतन सूची एफएसएसएआई पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी। केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) व स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री प्रतापराव जाधव ने आयुर्वेद आहार को निवारक स्वास्थ्य सेवा व संतुलित, सतत जीवनशैली की दिशा में महत्वपूर्ण बताया और नागरिकों से इसे अपनाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पारंपरिक ज्ञान आधारित यह आहार पद्धति शरीर को पोषण, रोग प्रतिरोधक क्षमता और पाचन में सहायक है। आयुष मंत्रालय के सचिव श्री वैद्य राजेश कोटेचा ने इसे पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक नियामक व्यवस्था के बीच सेतु बताया, जिससे एफबीओ को स्पष्टता और उपभोक्ताओं को आयुर्वेद-आधारित पोषण पर विश्वास मिलेगा। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान (डी नोवो विश्वविद्यालय) के कुलपति प्रो. संजीव शर्मा ने बताया कि मंत्रालय के मार्गदर्शन में एनआईए ने प्रामाणिक ग्रंथों से पारंपरिक सूत्रीकरणों को वैज्ञानिक सत्यापन सहित संकलित किया है, जो निर्माताओं के लिए मार्गदर्शक और आमजन के लिए सुरक्षित, समय-परीक्षित विकल्प होंगे। आयुर्वेद आहार संतुलन, मौसमी उपयुक्तता और प्राकृतिक सामग्री व जड़ी-बूटियों के चिकित्सीय लाभों पर आधारित है, जो परंपरा और आधुनिक आहार आदतों में सामंजस्य स्थापित करता है।

दौराई-गोड्डा साप्ताहिक एक्सप्रेस रेलगाड़ी का शुभारंभ

भारतीय रेल द्वारा अपने सम्मानित रेल यात्रियों की सुविधा का ध्यान रखते हुए गाड़ी संख्या 19603/19604 दौराई (अजमेर)-गोड्डा साप्ताहिक एक्सप्रेस रेलगाड़ी का नियमित सेवा निम्नलिखित समय सारिणी के अनुसार होगी, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

गाड़ी सं. 19603/19604 दौराई (अजमेर)-गोड्डा (साप्ताहिक) एक्सप्रेस की नियमित सेवा

गाड़ी संख्या - 19603 दौराई (अजमेर)-गोड्डा साप्ताहिक एक्स.			गाड़ी संख्या - 19604 गोड्डा-दौराई (अजमेर) साप्ताहिक एक्स.	
आगमन	प्रस्थान	स्टेशन	आगमन	प्रस्थान
----	15:30 (रवि)	दौराई	17:20 (बुध)	----
01:00	01:02	अलीगढ़ जं.	04:00	04:02
02:03	02:05	टूण्डला जं.	02:08	02:10
03:05	03:07	इटावा जं.	00:50	00:52
04:50	04:55	गोविन्दपुरी	22:30	22:35
05:58	06:00	फतेहपुर	21:05	21:07
07:20	07:25	सूबेदारगंज	19:55	20:00
08:40	08:42	मिर्ज़ापुर	18:30	18:32
09:10	09:12	चुनार जं.	17:48	17:50
22:20 (सोम)	----	गोड्डा	----	05:00 (मंगल)

दौराई (अजमेर) से:- गाड़ी संख्या 19603, दिनांक 03.08.2025 से प्रत्येक रविवार।

गोड्डा से:- गाड़ी संख्या 19604, दिनांक 05.08.2025 से प्रत्येक मंगलवार।

गाड़ी संरचना:- सामान्य श्रेणी- 04, स्लीपर- 07, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी इकोनॉमी कोच- 03, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी- 03, वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी- 02 एवं पेन्ट्रीकार- 01

नोटः- ट्रेनों से सम्बंधित जानकारी हेतु हेल्पलाइन 139 या Rail Madad Mobile App या वेबसाइट railmadad.indianrailways.gov.in का प्रयोग करें।

उत्तर मध्य रेलवे

@CPRONCR North central railways www.ncr.indianrailways.gov.in 1361/25(A)

Railway authorities and State Pollution Control Board hold joint meeting on Plastic Waste Management

Source/NFR- In a major step towards environmental sustainability and waste management, the Northeast Frontier Railway (NFR) held a collaborative meeting with officials from the Assam State Pollution Control Board (PCBA) & representatives of M/s Kusum Udyog, Rangia, a PCBA-approved recycling agency. The meeting, chaired by Shri M. Kalimuthy CME / EnHM/ NFR, focused on initiatives to make Guwahati Railway Station the first plastic-free railway station in India. During the meeting, key strategies were discussed to ensure efficient segregation, shredding, washing, and recycling of plastic waste collected from trains and station premises. M/s Kusum Udyog will be submitting a comprehensive proposal for handling, cleaning, and transporting plastic waste from the station's garbage storage area to an authorized recycling unit. The agenda also included reviewing current waste disposal practices, identifying high-impact areas and formulating a joint action plan to minimize single use plastics and enhance sustainable practices. Furtherly, the Scouts and Guides of NFR organized a public awareness activities such as placard displays, Nukkad Natak (street plays) and drama performances. Immediate steps have also been initiated to inspect and ensure proper functioning of the Effluent Treatment Plant (ETP) and Sewage Treatment Plant (STP). The Pollution Control Board commended these efforts & emphasized the importance of stricter compliance and regular monitoring. It also assured technical support and policy guidance to facilitate the adoption of eco-friendly alternatives and waste treatment solutions.

Guwahati Railway Station, the largest and most strategic station under the NFR zone, serves as a vital gateway to the Northeast, handling more than 100 trains daily including Rajdhani Express and Vande Bharat Express. Known for its high footfall, modern infrastructure and commitment to eco-friendly operations, the station is working in close partnership with the Assam Pollution Control Board and local industries to become a 100% plastic waste-managed and recycled station.

This meeting marks a significant step toward building a cleaner and greener railway ecosystem. It also reinforces the government's broader commitment to reducing plastic pollution through collaborative and coordinated efforts between agencies.

38 Railway Projects Worth ₹89,780 Crore Sanctioned in Maharashtra; Over 2,360 Km Commissioned

Source/PIB- Budget allocation for Maharashtra's railway infrastructure and safety works has risen significantly, from an annual average of ₹1,171 crore (2009–14) to ₹23,778 crore in 2025–26, which is more than a 20-fold increase. New track commissioning also grew by over three times, from 292 km (58.4 km/year) during 2009–14 to 2,292 km (208.36 km/year) in 2014–25. As of April 1, 2025, 38 projects (11 New Lines, 2 Gauge Conversion, and 25 Doubling) are sanctioned for Maharashtra, with a total length of 5,098 km and a cost of ₹89,780 crore. So far, 2,360 km have been commissioned, and an expenditure of ₹39,407 crore has been incurred up to March 2025. The breakdown of this expenditure is as follows: ₹10,504 crore for New Lines, ₹4,286 crore for Gauge Conversion, and ₹24,617 crore for Doubling/ Multitracking projects.

Recently Completed and Ongoing Projects- Ten projects have been recently completed, including the Jabalpur–Gondia Gauge Conversion (300 km, ₹2,005 Cr), Chhindwara– Nagpur Gauge Conversion (150 km, ₹1,512 Cr), and Daund–Gulbarga Doubling (225 km, ₹3,182 Cr). Key ongoing works include the Bhusawal–Khandwa 3rd & 4th Line (131 km, ₹3,285 Cr) and a survey for the Murtizapur–Achalpur Gauge Conversion.

Key Sanctioned Projects - A large number of projects have been sanctioned to further expand the railway network. These include seven New Line projects:

- ***Ahmednagar–Beed–Parli Vaijnath (261 km, ₹4,957 Cr)***
- ***Baramati–Lonand (64 km, ₹1,844 Cr)***
- ***Wardha–Nanded (284 km, ₹3,445 Cr)***
- ***Dhule–Nardana (51 km, ₹1,171 Cr)***
- ***Manmad–Indore (309 km, ₹16,321 Cr)***
- ***Wadsa-Gadchiroli (52 km, ₹1,886 Cr)***
- ***Jalna-Jalgaon (174 km, ₹5,804 Cr)***

There are also several doubling and multi-tracking projects, such as:

- ***Pune–Miraj–Londa Doubling (466 km, ₹6,463 Cr)***
- ***Daund–Manmad Doubling (236 km, ₹30,376 Cr)***
- ***Kalyan-Kasara 3rd line (68 km, ₹1,433 Cr)***
- ***Wardha-Nagpur 3rd line (76 km, ₹698 Cr)***
- ***Manmad Jalgaon 3rd line (160 km, ₹1,677 Cr)***
- ***Kazipet-Ballarshah 3rd line (202 km, ₹3,183 Cr)***
- ***Jalgaon-Manmad 4th Line (160 km, ₹2,574 Cr)***

The High-Speed Bullet Train project in Maharashtra has completed 100% of its land acquisition, and construction work is currently in progress. The Western Dedicated Freight Corridor (DFC) has a 178 km section in Maharashtra, with 76 km already commissioned, and the remaining work is underway. These projects are expected to enhance capacity, reduce bottlenecks, and boost the economy. Additionally, 27 multi-tracking projects spanning 1,991 km and costing approximately ₹47,126 crore were sanctioned from FY 2022–23 to the current FY.

Central Railway organises Station Mahotsav at Byculla Station.

Source/CR- After the successful completion of Station Mahotsav events at 7 stations of Central Railway, Station Mahotsav was organised at Byculla Station on Mumbai Division on 23.07.2025 as part of the Station Mahotsav Celebrations of Railway Stations as advised by Railway Board. 7 Station Mahotsavs had recently been held at Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus, Nagpur, Reay Road, Asangaon, Vasind, Kasara and Igatpuri stations of Central Railway. A total of 15 stations on all 5 Divisions of Central Railway are among those identified for celebrations of Station Mahotsavs. Byculla Station is one of the oldest Railway stations in India, in operation since 1853. It was one of the halts of the first train that ran on the Indian subcontinent from Bori Bunder to Tannah (known as Thane now) on 16th April 1853. The current station building built in 1891 is a fine example of Victorian architecture. The Station wore a festive look with decorations and a grand rangoli as part of the Station Mahotsav celebrations. The Celebrations featured a Heritage exhibition wherein various artefacts belonging to the GIPR era were displayed. Sketches and Black n White photos of Old Byculla station were also displayed. The highlight of the exhibition was a GIPR monogram made of gun metal and an Old ticket window frame made of gunmetal which was a part of Byculla station till a few years back. Among the items on display were a GIPR era Bench, Iron sleepers, Old Telephone instrument, Official Stamps and Measuring weights made of brass, Gate Keeper's badge, Old Carraige & Wagon plates, Rotary switches, Engineering wooden scale box and Old track hand levers used for changing the track. Miniature models of Steam locomotives of the GIPR era were also part of the display. In addition to the Old, the exhibition also displayed a model of the Vande Bharat Trains in service presently and a model of the Bullet Train expected to be operational in the near future. Selfie points were also put up for visitors to take photos as a remembrance. The exhibition, was a trip down memory lane with a large number of visitors including Students, Office going people, Professionals, Heritage enthusiasts, Rail Fans and passengers. The Station Mahotsav Celebrations were a memorable blend of history, culture, education, & celebration truly befitting stations that have served the passengers of Indian Railways with dedication for over a century.

Indian Railways to Launch Dedicated Online Ticketing Portal for MPs

Source/RSB- Indian Railways is developing a dedicated online ticket booking portal exclusively for Members of Parliament (MPs), aimed at streamlining their travel arrangements. This initiative will cater to both Lok Sabha and Rajya Sabha members, offering them a seamless and hassle-free ticket booking experience. In a written reply to the Lok Sabha on Wednesday, July 23, Railway Minister Ashwini Vaishnaw confirmed the development. He stated that the Railways is in the process of creating a software system that will allow both sitting and former parliamentarians to reserve and cancel train tickets online at their convenience.

Benefits of the Portal:

- ***Easy and convenient booking and cancellation for sitting and former MPs.***
- ***Saves time by removing the need to visit reservation counters.***
- ***Dedicated access ensures seamless and prioritized service.***
- ***Paperless system increases transparency and operational efficiency.***
- ***Enables timely and well-planned travel for parliamentary responsibilities.***
- ***Customized & user-friendly interface designed specifically for MPs.***

RAILWAY PROTECTION FORCE AND NATIONAL COMMISSION FOR WOMEN STRENGTHEN RESOLVE AGAINST HUMAN TRAFFICKING

Source.PIB- On the occasion of World Day Against Trafficking in Persons, a renewed Memo-randum of Understanding (MoU) was signed between the Railway Protection Force (RPF) and the National Commission for Women (NCW) in the august presence of Hon'ble Union Minister for Railways, Shri Ashwini Vaishnaw. Sharing the development on social media, the Union Minister stated that the MoU aims to strengthen the capacity of RPF personnel to effectively prevent the trafficking of women and children as well as other crimes against women. The MoU was signed by Smt. Shivani Dey, Deputy Secretary, NCW, and Shri S. Sudhakar, DIG/Projects, RPF. On this occasion, a special booklet on antihuman trafficking, prepared by the NCW, was also released. Smt. Vijaya Rahatkar, Chairperson of NCW, underscored the seriousness of the issue by stating that human trafficking continues to be one of the gravest human rights violations, with women and girls being the most frequent targets. She emphasized the pivotal role of the RPF in early detection and intervention. She also appreciated the painstaking nationwide efforts of the RPF in rescuing trafficked and lost/runaway children from across the country, which has led to the rescue of more than 65,000 such children over the past four and a half years. The MoU facilitates the organization of structured

training programs and sensitization initiatives for RPF personnel. Public awareness efforts, including the dissemination of informational materials at railway stations & on trains, will also be undertaken. Additionally, Anti-Human Trafficking Units (AHTUs), already operational at over 750 locations, will be leveraged to strengthen surveillance and ensure immediate response to suspected cases. This collaborative effort reflects a shared national commitment to safeguarding vulnerable communities and advancing a zero-tolerance approach toward human trafficking through one of India's most vital public service systems—the Indian Railways.

MS. SONALI MISHRA, IPS, ASSUMES CHARGE AS DIRECTOR GENERAL, RAILWAY PROTECTION FORCE

Source/PIB- The Railway Protection Force (RPF) welcomes Ms. Sonali Mishra, IPS (1993 batch, Madhya Pradesh cadre) as the new Director General of RPF, marking a historic first in the 143-year journey of the Force. The Appointments Committee of the Cabinet approved her appointment as DG/RPF until her superannuation on October 31, 2026. An officer known for her professionalism, dedication and leadership across key policing roles, Ms. Mishra brings over three decades of distinguished service to the post. Prior to this assignment, she served as Additional Director General of Police (Selection/ Recruitment) with the additional charges of ADG, Police Training & Research Institute, Bhopal and Director of the Madhya Pradesh Police Academy, Bhopal. She has also served in the CBI, BSF & has international exposure of having served with the United Nations Peacekeeping Mission in Kosovo. She has been honoured with prestigious awards including the President's Police Medal for Distinguished Service and the Police Medal for Meritorious Service in recognition of her commitment to excellence & professionalism. The Railway Protection Force, mandated with the security of railway property, passenger safety and crime prevention across one of the world's largest rail networks, stands to benefit from her visionary & inclusive leadership. Her extensive experience across state and central police organizations is expected to bring renewed momentum to modernization, capacity building & community engagement within the Force. In particular, her focus will be on strengthening RPF's initiatives in leveraging cutting-edge technology and enhancing its role in preventing organised crime such as human trafficking and crimes against vulnerable passengers.On assuming charge, Ms. Mishra expressed gratitude for the opportunity to serve and reaffirmed her commitment to upholding the values of vigilance, courage and service that define the RPF's motto "Yasho Labhasva"

Mrs. Ity Pandey, IRTS Takes Charge as PCCM (Principal Chief Commercial Manager), South Central Railway

Source/RSB- Mrs. Ity Pandey, an officer of the 1995 batch of the Indian Railway Traffic Service (IRTS), has assumed charge as the PCCM (Principal Chief Commercial Manager), South Central Railway. She was a gold medalist in psychology from the University of Allahabad. Before taking charge as Principal Chief Commercial Manager, SCR, Mrs. Pandey served as Divisional Railway Manager, Bhusawal Division. She also held the post of Chief Commercial Manager (Passenger Services) at the Central Railway Headquarters and has previously occupied various significant roles in Central and Western Railways, including Chief Commercial Manager (Freight), Deputy Chief Commercial Manager, Senior Divisional Commercial Manager, Divisional Commercial Manager, and Assistant Commercial Manager. In addition to her expertise in the Commercial Department, her experience extends to the Safety and Vigilance departments. Mrs. Ity introduced Rudra, a 'hospital on wheels' initiative, to provide accessible health-care to railway workers and their families in remote areas while posted as Divisional Railway Manager, Bhusawal. This mobile clinic is changing health-care delivery and offering timely medical services directly to those who need them the most. She has been honoured with General Managers Award (twice), Ministry of Railways Award for excellence and Meritorious Services 2007 and Women Achievers Award 2016. On 17/6/25, received the Rail Mantri Rajbhasha Rajat Padak. She was instrumental in setting up of the first Unreserved Ticketing System in Mumbai. As Claims Officer, played a key role in settling claims for all victims of the Elphinstone Road stampede, an episode not covered under the Railway Act for compensation, and managed this without involvement of any lawyer. As Chief Commercial Manager (Freight), authored a book titled Riding the Freight Train, a comprehensive overview of Freight Operations over Western Railway. Recognized among the 24 Bureaucrat Change makers of 2024 in the Bureaucrats Annual List 2024—an honour that reflects her visionary leadership and relentless efforts in enhancing Passenger Services and Freight efficiency. As a Marathon Runner and the only lady Civil Servant to complete the Comrades Marathon in South Africa in 2023, she completed the grueling 88-kilometer distance in 11 hours and 47 minutes.

Aluabari Road - New Jalpaiguri 3rd and 4th Line approved by Union Cabinet To boost rail connectivity in Northeastern States

Source/RSB- The Union Cabinet has approved the 3rd and 4th railway line between Aluabari Road and New Jalpaiguri which marks a significant milestone in enhancing rail connectivity in the Northeastern region of India. Spanning a total length of 57 kilometres, under the jurisdiction of Northeast Frontier Railway, the project is approved at an estimated cost of approximately Rs. 1,786 crores. This project aims to address the growing demand for transportation infrastructure in one of the country's most vital regions. By introducing additional tracks, it will reduce congestion, allowing for more efficient and faster movement of both passenger and freight trains, thus cutting travel times and improving the overall reliability of services. The increased rail capacity will not only ease the burden on the existing infrastructure but will also facilitate the transportation of goods such as tea, timber & agricultural products, thus boosting the local and regional economy. This project is part of the Delhi – Guwahati High Density Network route and holds strategic importance due to its proximity to the international borders with Bhutan, Bangladesh and Nepal, providing vital access to these neighbouring regions. It passes through districts in Bihar (Kishanganj) & West Bengal (Jalpaiguri, Darjeeling and Uttar Dinajpur), serving as a crucial link for both passenger and freight transport. The infrastructure development will include 7 stations, 99 bridges and the construction of 3 Road Over Bridges and 8 Road Under Bridges. The project aims to facilitate the movement of 21.6 million tons of additional cargo, leading to a savings of Rs 2,551 crore in logistics costs. It will also contribute significantly to fuel conservation by saving 2.14 crore litres of diesel every year. In the broader context, the Aluabari Road – New Jalpaiguri 3rd and 4th Line project is poised to not only strengthen transportation infrastructure but also act as a catalyst for economic growth, regional integration and enhanced quality of life in the Northeast. This project will enhance the overall efficiency of the transportation network across Bihar, West Bengal and the Northeast, easing congestion on this crucial corridor that serves as a vital gateway between the eastern and NE region of India. NFR remains committed towards executing this project efficiently, ensuring maximum benefit to the region's connectivity and development.

Huppuguda Railway Station Being Redeveloped with an Expenditure of Rs. 26.81 Crores under Amrit Bharat Station Scheme

Source/RSB- A major transformation is in progress for Indian Railways with upgradation of railway stations on a massive scale, with a vision to provide worldclass facilities to the passengers. Under the "Amrit Bharat Station Scheme" (ABSS), 40 railway stations across Telangana are being redeveloped with an estimated cost of Rs 2,750 crores. The mission got a major boost when the Hon'ble Prime Minister, Shri Narendra Modi laid foundation stone for redevelopment of stations in the state of Telangana during August, 2023 and February, 2024. Recently, three Amrit stations (Begumpet, Warangal & Karimnagar) in Telangana were inaugurated by Hon'ble Prime Minister. Huppuguda Railway Station in Hyderabad Division of SCR is being redeveloped under Amrit Bharat Station Scheme (ABSS) with an approximate cost of Rs 26.81 Crores. Huppuguda station is a Suburban Grade-3 station located in southern part of Hyderabad city in Falaknuma – Kacheguda section and serves the passengers in and around the area. The average footfall at this station is 5,000 passengers per day and the commuters mainly travel from here to different parts of the city in suburban trains especially towards west part of the city like Hi-tech City, Lingampalli etc. for employment, business. Around 50 trains are dealt at this station per day including suburban trains.

Proposed Works under ABSS

- ***Provision of new façade***
- ***Development of station building near 2nd entry***
- ***Circulating area development***
- ***Provision of 12M FOB***
- ***Provision of 2 passenger lifts and 2 escalators***
- ***Improvements to platform surface***
- ***Provision of additional cover over platform***
- ***Interior renovations of concourse & waiting halls***
- ***Provision of toilets for Divyangjan***
- ***New signage boards and new furniture etc.***

Status of the Works

- ***Waiting hall improvements, 12M FOB girders launching work completed***
- ***Parking sheds, compound wall nearing completion***
- ***Lifts and escalators sheeting work is in progress***
- ***All the works are in progress simultaneously & are targeted to be completed by December 2025.***

13 Districts, 6 States, 574 Kms! Cabinet Approves Massive Rail Network Expansion

Source/PIB- The Cabinet Committee on Economic Affairs, chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi, has approved 4 (Four) projects of Ministry of Railways on 31st July, 2025 with total cost of Rs. 11,169 crore (approx.).

These projects include:

- Itarsi – Nagpur 4th Line
- Aurangabad (Chhatrapati Sambhajinagar)-Parbhani Doubling
- Aluabari Road- New Jalpaiguri 3rd and 4th Line
- Dangoaposi- Jaroli 3rd and 4th Line

The increased line capacity will significantly enhance mobility, resulting in improved operational efficiency and service reliability for Indian Railways. These multi-tracking proposals are poised to streamline operations and alleviate congestion. The projects are in line with the Prime Minister Shri Narendra Modiji's Vision of a New India which will make people of the region "Atmanirbhar" by way of comprehensive development in the area which will enhance their employment/ self-employment opportunities. The projects are planned on PM-Gati Shakti National Master Plan with focus on enhancing multimodal connectivity & logistic efficiency through integrated planning and stakeholder consultations. These projects will provide seamless connectivity for movement of people, goods, and services. The 4 (four) projects covering 13 Districts across the states of Maharashtra, Madhya Pradesh, West Bengal, Bihar, Odisha, and Jharkhand will increase the existing network of Indian Railways by about 574 Kms. The proposed multi-tracking project will enhance connectivity to approx. 2,309 villages, which are having a population of about 43.60 lakh. These are essential routes for transportation of commodities such as coal, cement, clinker, gypsum, fly ash, containers, agriculture commodities, and Petroleum products etc. The capacity augmentation works will result in additional freight traffic of magnitude 95.91 MTPA (Million Tonnes Per Annum). The Railways being environment friendly and energy efficient mode of transportation, will help both in achieving climate goals and minimizing logistics cost of the country, reduce oil import (16 Crore Litres) and lower CO2 emissions (515 Crore Kg) which is equivalent to plantation of 20 Crore trees.

Indian Railways Rapidly Emerging as a Global Exporter of Bogies, Coaches, Locomotives & Propulsion Systems under 'Make in India, Make for the World' Vision:

Rail Minister Applauds Alstom's Role in Building India's Global Rail Footprint

Source/PIB- Union Minister for Railways, Shri Ashwini Vaishnaw, visited Alstom's Savli facility in Vadodara, Gujarat — a key manufacturing hub for railway rolling stock in India. During his visit, the Minister reviewed the facility's operations with a specific focus on maintenance practices and appreciated Alstom's approach of designing customized solutions for each order. He noted that such innovative practices could be emulated by Indian Railways to enhance efficiency. In a significant move toward academic-industry collaboration, the Minister proposed developing a joint training programme between Alstom and Gati Shakti Vishwavidyalaya through a creative and collaborative framework. He also suggested that General Managers of all Production Units undertake training and exposure visits to the Savli facility. Discussions further included the potential use of sensors and artificial intelligence for preventive maintenance in railway systems. The Savli unit is currently engaged in the production of state-of-the-art commuter and transit train cars, fully aligned with the Government of India's Make in India and Aatmanirbhar Bharat initiatives. The facility exemplifies India's growing capabilities in advanced manufacturing and innovation, with over 3,400 Indian engineers working in collaboration with 21 Alstom sites globally. Since 2016, India has successfully exported 1,002 rail cars for international projects. Of these, 450 rail cars manufactured at the Savli unit were exported to Australia for the Queensland Metro project, underscoring India's role as a trusted global supplier of modern rail systems.

Expanding Global Footprint of Indian Rail Components

The Savli facility has also exported more than 3,800 bogies to countries including Germany, Egypt, Sweden, Australia, and Brazil, along with over 4,000 flatpacks (modular components) to Vienna, Austria. In addition, Alstom's Maneja unit has exported over 5,000 propulsion systems to various global railway projects.

Designed in India, Installed Worldwide

India is currently leading 27 international signalling projects while supporting an additional 40 globally. The Digital Experience Centre in Bengaluru is driving innovation by supporting over 120 global projects, focusing on next-generation signalling technologies such as IoT, AI, blockchain, and cybersecurity. "Design, Develop, and Deliver from India to the World"

India's rail manufacturing and export portfolio continues to grow:

- **Metro Coaches exported to Australia and Canada**
- **Bogies shipped to the UK, Saudi Arabia, France, and Australia**
- **Propulsion Systems supplied to France, Mexico, Romania, Spain, Germany, and Italy**
- **Passenger Coaches delivered to Mozambique, Bangladesh, and Sri Lanka**
- **Locomotives exported to Mozambique, Senegal, Sri Lanka, Myanmar, Bangladesh, and the Republic of Guinea**

Boosting Local Industry and Employment

The Savli manufacturing ecosystem is supported by a robust supplier network, including companies such as Integra, Anovi, Hind Rectifier, Hitachi Energy, and ABB — all contributing in areas such as fabrication, interiors, and electrical systems. Speaking to the media, the Union Minister stated that the positive impact of the Make in India and Make for the World initiatives is clearly visible in the Indian Railways manufacturing sector. He emphasized that exports of railway components are generating significant employment opportunities and enabling Indian engineers and workers to acquire global-level expertise — a major achievement for the Make in India mission.

IRCON International Secures ₹670 Crore Contract for Mumbai Metro Line 6 Project

Source/RSB- IRCON International Limited has been awarded a significant contract worth ₹670 Crore by the Mumbai Metropolitan Region Development Authority (MMRDA) for extensive work on the Mumbai Metro Line 6, which connects Swami Samarth Nagar to Vikhroli. The contract encompasses a comprehensive scope, including the design, manufacture, supply, installation, integration, testing, and commissioning of critical infrastructure for the metro line. Key responsibilities will cover the power supply and traction systems, complete electrical and mechanical (E&M) works, and the installation of all lifts and escalators required for the corridor. The project is set to be executed within a completion period of 104 weeks. Following the commissioning, the agreement also includes a two-year Defect Liability and Maintenance Period (DLMP), which will be succeeded by an additional five years of comprehensive maintenance, ensuring the long-term operational integrity of the systems.This strategic win underscores IRCON's role in developing modern urban infrastructure. In securing the contract, the company affirmed its dedication to the project's success, stating it is "committed to powering Mumbai's urban mobility!"

CONCOR Launches End-to-End Rail Parcel Service to Boost Logistics for E-commerce and MSMEs

Inaugural service between Mumbai and Kolkata marks a major initiative to enhance supply chain efficiency and promote ease of doing business through a sustainable, cost-effective model.

Source/RSB-In a landmark initiative set to transform India's long-haul logistics sector, the Container Corporation of India (CONCOR) has officially launched its dedicated End-to-End Parcel Service. The inaugural run, utilizing Indian Railways' Parcel Van (VP), commenced its journey from BIRD (Mumbai) to SGYT (Kolkata) on August 7, 2025.This new service leverages the extensive speed, reliability, and reach of the Indian Railways network, operating under the JPP-RCS time table to guarantee fixed transit schedules and timely delivery. The model is designed to be highly cost-efficient, presenting a powerful logistics solution for a wide range of businesses.A key feature of the service is its seamless integration of rail and road transport. CONCOR is offering a complete door-to-door solution, with cargo being picked up directly from the customer's location and delivered to the final destination's doorstep. This effectively bridges the logistics gap for small to mid-sized shipments, making it an ideal choice for the burgeoning e-commerce sector and Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs).To further enhance user experience and supply chain visibility, the service includes modern features such as real-time tracking and advance booking capabilities.By providing a reliable and sustainable alternative to traditional road transport, this initiative is a major step forward in promoting ease of doing business in the country. CONCOR's end-to-end parcel service is poised to significantly improve supply chain efficiency, offering a robust framework for the future of domestic cargo movement.

RITES Ltd. Reports 7.9% Growth in Operational Profits for Q1FY26

Source/ RSB- RITES Ltd., a leading transport infrastructure consultancy and engineering firm, announced strong standalone and consolidated financial results for the quarter ended June 30, 2025, highlighted by a significant increase in operational profitability and a healthy order book.

The Takeaways

- *7.9% YoY jump in Operational Profits on account of better execution*
- *Order Book of ₹8790 crore; Secured 150+ orders worth ₹451 crore in Q1*
- *Interim Dividend of ₹1.30 per share*

Q1FY26 Financials (Consolidated)

- *Operating Revenue at ₹490 crore*
- *EBITDA at ₹117 crore with Margins of 23.8%*
- *PAT at ₹91 crore with Margins of 17.8%*

Commenting on the results, **Mr. Rahul Mithal, Chairman and Managing Director,** RITES Limited, said, "The results have been flat, underscoring the need for expeditious execution, with our Order Book being young; having secured about 300 orders totalling to ₹3500 crore in the last 2 quarters of FY25."

Financial Performance in Q1FY26 -

RITES operating revenue (consolidated), excluding other income, stands at ₹490 crore in Q1FY26 as against ₹486 crore in Q1FY25, a marginal increase by 0.8%. Total revenue is ₹512 crore as against ₹508 crore in Q1FY25. EBITDA and PAT stand at ₹117 crore and ₹91 crore with margins of 23.8% and 17.8%, respectively, up by 7.9% and 0.5% respectively against Q1FY25. The sustained Y-o-Y performance is attributed to enhanced execution efficiency across key consultancy projects, reflecting the operational focus and delivery capabilities, and addition to the leased locomotives.

Standalone -

Operating revenue, excluding other income, stands at ₹456 crore in Q1FY26 against ₹454 crore in Q1FY25. Total standalone revenue is ₹476 crore against ₹475 crore in Q1FY26. EBITDA and PAT, with respective margins of 18.5% and 14%, stand at ₹84 crore and ₹67 crore up by 7.6% and 2.8%, respectively from Q1FY25.

Segmental Performance -

The Consultancy business continues to provide the highest revenue to the company and achieved the revenue of ₹262 crore with margins at 32.2%. The increase in Consultancy revenue is attributable to better execution. With the fleet of 88 locomotives, leasing revenue stands at ₹43 crore, maintaining the margins of 38.4%. Turnkey revenue stands at ₹148 crore, while exports have commenced in Q2FY26.

Dividend -

The Board of Directors has declared the interim dividend of ₹1.30 per share amounting ₹62.5 crore. The record date for the purpose of payment of dividend is 12 th August, 2025.

Order Book -

The company has secured more than 150 orders (including extension of works) worth more than ₹451 crore in Q1FY26, thereby achieving the order book of ₹8790 crore as on June 30 th, 2025.

Outlook -

On the growth prospects, Mr. Mithal said, *"While maintaining the trend of now more than 1 order a day, concerted efforts will be made for steady sequential growth, aiming for a substantial improvement over last year."*

'विकसित भारत' की प्रेरणा
'विकसित उत्तर प्रदेश' का प्रण
1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर
8.50 लाख+ सरकारी नौकरियां
यूपी : ब्रह्मोस निर्माण का नया डेस्टिनेशन
16 घरेलू एयरपोर्ट, 5 अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट
7 एक्सप्रेसवे संचालित, 15 एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन/प्रस्तावित
96 लाख+ MSME इकाइयां
2 एम्स एवं 80 मेडिकल कॉलेज संचालित
सर्वाधिक 6 शहरों में मेट्रो रेल सेवा
BRAHMOS
"स्वतंत्रता दिवस उन असंख्य ज्ञात-अज्ञात बलिदानियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का अवसर है, जिन्होंने राष्ट्र प्रथम के लिए सर्वस्व समर्पित कर दिया। जब विभाजनकारी शक्तियां जाति-धर्म-सम्प्रदाय के नाम पर देश को तोड़ना चाहती हैं, विदेशी शक्तियां हमारी संकल्प शक्ति की परीक्षा लेना चाहती हैं, तब बाबा साहेब डॉ. भीमराव रामजी आम्बेडकर की प्रेरणा से संचालित आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के वर्ष 2047 तक 'विकसित भारत' के निर्माण के विजन के अनुरूप प्रदेश की महान जनता के पास पुन: यह अवसर है कि वह 'पंचप्रण' को आत्मसात कर इस पुण्य धरा को राष्ट्रचेतना की भूमि में परिवर्तित कर 'विकसित उत्तर प्रदेश' के मिशन को सिद्ध करे। राष्ट्र एवं संविधान के रक्षकों के प्रति यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी।"
जय हिंद
79वें स्वतंत्रता दिवस
की
हार्दिक शुभकामनाएं
- योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश
UPGovtOfficial
CMOUttarpradesh
CMOfficeUP
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश